● वर्ष-5

● अंक-212

रायपुर, बुधवार
22 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› ऐतिहासिक गलती के लिए ...

त्रिपुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अहम संदेश

लड़खड़ाती दुनिया को भारत दिखाएगा रास्ता

अगरतला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने मंगलवार को कहा कि दुनिया वर्तमान में लड़खड़ा रही है और शासन, धर्म और विज्ञान की विभिन्न प्रणालियों के साथ 2000 वर्षों के प्रयोगों के बाद भारत के ज्ञान की तलाश कर रही है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के मोहनपुर स्थित मां सौंदर्या चिन्मयी मंदिर के प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेकम कार्यक्रम में बोलते हुए, भागवत ने टिप्पणी की कि सदियों से कई वैश्विक मॉडलों को आजमाया गया है, लेकिन वे स्थायी शांति और संतोष स्थापित करने में विफल रहे हैं।

मोहन भगवत ने कहा कि 2000 वर्षों से दुनिया ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। पहले सब कुछ राजा को दिया जाता था। लोगों का मानना ??था कि राजा का होना अच्छा है, लेकिन बाद में राजा खुद अपनी प्रजा को लूटने लगा। इसलिए उन्होंने कहा, ईश्वर ही राजाओं का राजा है। इस प्रकार, ईश्वर के प्रति भक्ति पर आधारित विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने जीवन में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, और अंततः रक्त की नदियाँ बहा दीं।

उन्होंने आगे मानव पीड़ा को दूर करने में वैज्ञानिक युग की सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाद में उन्होंने कहा, हम वैज्ञानिक हैं। हम ईश्वर में तभी विश्वास करेंगे जब ईश्वर प्रयोगशाला में हमारी परीक्षण नलियों में प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं। फिर विज्ञान का युग शुरू हुआ। बहुत सारी सुख-सुविधाएँ और विलासिताएँ पैदा हुईं, लेकिन संतोष नहीं है। पीड़ा अभी भी है, परिवार टूट रहे हैं, और अपराध बढ़ रहा है। युद्ध, एक बार शुरू हो जाने पर, रुकते नहीं हैं, और युद्ध कभी नहीं रुकते। जितना अधिक विकास होता है, उतना ही अधिक पर्यावरण नष्ट होता है।

भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता अब इन लंबे प्रयोगों के परिणामों का सामना कर रही है, और कहा कि अब, ऐसे प्रयोगों के 2000 वर्षों के बाद, दुनिया लड़खड़ा रही है और भारत के ज्ञान की लालसा कर रही है। यह भारत का कर्तव्य है, क्योंकि यही भारत के जीवन का उद्देश्य है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस धार्मिक आयोजन में उपस्थित थे।

पूरा बंगाल तय कर बैठा है, दीदी को हटाने का समय आ गया

■ दार्जिलिंग की रैली में बोले शाह

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और दार्जिलिंग में आयोजित जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर तीखा बयान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की मांग अब तेज हो रही है और जनता परिवर्तन की दिशा में सोच रही है। अमित शाह ने गोरखा समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो गोरखा बहनों और भाइयों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

अमित शाह ने अपने संबोधन में दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद छह महीनों के भीतर गोरखा समुदाय से जुड़ी पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे लोगों के जीवन में संतोष और स्थिरता आ सके।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) दोनों पर गोरखा समुदाय और दार्जिलिंग क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप रहा है। शाह के अनुसार, इन समस्याओं का समाधान

भाजपा अपनी सरकार बनने के बाद तय समयसीमा में करने का प्रयास करेगी।

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर बंगाल के लोगों से अपील की कि एक बार फिर भाजपा को अवसर दिया जाए, ताकि विकास और समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा उत्तर बंगाल वालों, एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए। तीन चुनावों से दार्जिलिंग तो कमल फूल पर वोट कर ही रहा है, लेकिन इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को हटाने का समय आ गया है।

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बजट आवंटन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल सरकार ने उत्तर बंगाल, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जबकि मदरसों और अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए 5800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि उत्तर बंगाल और गोरखा समुदाय के साथ न्याय की शुरुआत अब से होगी।

शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में कई महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने विशेष रूप से संदेशखाली मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में अपराध करने वाले हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा और भाजपा की सरकार बनने पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी।

कभी लौह अयस्क का केंद्र रहा कुल्टी टीएमसी राज में बंदी की कगार पर

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और दार्जिलिंग के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी कुल्टी देश में लौह अयस्क उत्पादन का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण यह क्षेत्र अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है।

अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में औद्योगिक विकास की अनदेखी की गई है, जिससे कई पारंपरिक उद्योगों पर संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सही नीतियां अपनाई जातीं, तो कुल्टी जैसे क्षेत्र आज भी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल भाजपा उम्मीदवार को विधायक बनाने या पार्टी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना है।

अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 23 तारीख को कमल के निशान पर वोट दें और चार मई को भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में मौजूद हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और नगर निगमों के चुनाव का एलान

शिमला। हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में चुनाव 17 मई 2026 को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मंगलवार को चार नगर निगम (सोलन, मंडी, धर्मशाला व पालमपुर) समेत 47 नगर पंचायत और नगर परिषदों में इलेक्शन की तारीखों का एलान कर दिया है। इसी के साथ शहरी निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।

इस दौरान 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शिमला में प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगम के अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। इनमें पुरुष 1.80,963 मतदाता और महिला 179882 मतदान का प्रयोग करेंगे। 18 वर्ष वाले 1808 मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। कोई भी मतदाता सारथी ऐप में भी अपना और परिवार का नाम देख सकता है।नामांकन पत्र 29 व 30 अप्रैल और 2 मई (दोपहर 3 बजे तक) भरे जाएंगे। इनकी जांच 4 मई को सुबह 10 बजे से होगी। नामांकन वापस लेने का समय 6 मई (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक) निर्धारित है। नामांकन वापसी के बाद उसी वक्त चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 29 अप्रैल को करना होगा, जबकि 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

श्रवण कुमार बने जेडीयू विधायक दल के नेता

पटना। श्रवण कुमार को बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) विधायक दल का नेता चुना गया है। विधानसभा द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। यह कदम जेडीयू की उस बैठक के एक दिन बाद उठाया गया है, जिसमें पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार को नेतृत्व पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का सामाजिक पृष्ठभूमि और गृह क्षेत्र नीतीश कुमार के समान ही है। बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा, श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 2025 के चुनावों में लगातार आठवीं बार अपनी सीट जीती।

ऐसी व्यापक धारणा थी कि श्रवण कुमार उपमुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बजाय, पार्टी ने विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी को उपमुख्यमंत्री पदों के लिए चुना। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि निशांत कुमार द्वारा कोई भी पद स्वीकार न करने के बाद, श्रवण कुमार को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, अंततः उन्हें इस पद के लिए नहीं चुना गया। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड की बैठक में पार्टी विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया। नीतीश कुमार ने भी बैठक को संबोधित किया।

महिला आरक्षण पर खरगे का भाजपा पर हमला, कहा-

तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ धोखा है

चेन्नई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन से जोड़ने की आलोचना करते हुए इसे एक खतरनाक खेल बताया, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु जैसे राज्यों को दंडित करता है। 21 अप्रैल को तमिलनाडु के वेलाचेरी में एक चुनावी रैली में बोलते हुए, खर्गे ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खारिज होने का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़कर एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की। इसका मतलब है तमिलनाडु जैसे राज्यों को दंडित करना, जिन्होंने सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण किया। विपक्ष एकजुट रहा, दिल्ली में कांग्रेस ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, और डीएमके, टीएमसी, एसपी सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर विधेयक को विफल किया।

खरगे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रशंसा करते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह जनविरोधी और दक्षिण विरोधी है, इसलिए उन्होंने विधेयक को फाड़कर जला दिया। यह देश के हर नागरिक की जीत है। यह संघवाद और न्याय की जीत है। हमने पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह कांग्रेस की उपलब्धि है, प्रधानमंत्री मोदी की नहीं। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया को देश के साथ धोखाधड़ी बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित तो हुआ, लेकिन लागू नहीं हुआ। खरगे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लागू क्यों नहीं किया?

प्रमुख समाचार

बिहार में सम्राट चौधरी सरकार की पहली अग्निपरीक्षा 24 को

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नवगठित भाजपा-आधारित एनडीए सरकार का 24 अप्रैल को विधानसभा के विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा। कई घटक दलों की मजबूत स्थिति को देखते हुए सरकार के फ्लोर टेस्ट में आसानी से पास होने की उम्मीद है। बांकीपुर विधानसभा सीट अभी खाली है क्योंकि इसके विधायक नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाद में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। ऐसे में राज्य विधानसभा में एनडीए विधायकों की संख्या 201 है, जबकि विपक्ष के पास 243 सदस्यीय विधानसभा में 41 विधायक हैं। हालांकि, विपक्ष नई सरकार पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। केंद्र और बिहार सरकारें भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 मई को दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हो सकते हैं।

स्टालिन ने डीएमके गठबंधन को समर्थन देने का किया आग्रह

चेन्नई। तमिलनाडु में मंगलवार को विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रचार के अंतिम दिन मतदाताओं से अंतिम अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य के अधिकारों, संस्कृति और विकास की रक्षा के लिए डीएमके-नीत गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया। मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी सरकार की उपलब्धियों बताई। उन्होंने कहा जब लोग मुझे मेरे पिता से भी अधिक खतरनाक कहते हैं, तो मैं इसे एक अनुस्मारक के रूप में देखता हूं कि मैं उन लोगों के लिए खतरा हूं जो तमिलनाडु को धोखा देना चाहते हैं या उसके विकास में बाधा डालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने डीएमके पर लगे हिंदू विरोधी आरोपों को खारिज किया और भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु कई अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 13 की मौत

त्रिशूर (केरल)। केरल के त्रिशूर जिले के मुंडथिक्कोडु इलाके में मंगलवार को एक पटाखा निर्माण यूनिट में भीषण विस्फोट गया। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब शहर में आयोजित होने वाले वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम की तैयारियां चल रही थीं। इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। घटनास्थल पर पहुंचे राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के समय यूनिट में करीब 40 लोग काम कर रहे थे, क्योंकि आयोजकों द्वारा कर्मचारियों के लिए दोपहर का भोजन लाया गया था। अधिकारी ने कहा, हमें सूचना मिली है कि सात लोग वहां से भागने में सफल रहे।बताया जा रहा है कि यह विस्फोट उस पटाखा इकाई में हुआ, जहां त्रिशूर पूरम के थिरुवंबाडी गुट के लिए आतिशबाजी के सैंपल तैयार किए जा रहे थे। इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसमें आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। प्रारंभिक जानकारी में लगभग 40 लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी, जिनमें से कम से कम आठ की हालत गंभीर बताई गई थी।

सीजफायर पर संकटः शांति वार्ता पर ईरान की चुप्पी

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा दो सप्ताह का संघर्षविराम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के मुताबिक, यह सीजफायर बुधवार सुबह खत्म होने वाला है, लेकिन शांति की उम्मीदें अब धुंधली पड़ती दिख रही हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिनिधि और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की रवानगी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर पूरी तरह चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर साफ किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्षविराम भारतीय समयनुसार बुधवार सुबह 5:20 बजे समाप्त हो जाएगा। यदि समय सीमा समाप्त होने से पहले कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, तो दोनों देशों के बीच फिर से सीधी जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि दो सप्ताह के इस सीजफायर के खत्म होने से पहले ईरान का बातचीत की मेज पर आना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी तक वॉशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं।

खरगे ने पीएम मोदी को बताया आतंकवादी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का एक बयान इस वक्त देशभर में सुर्खियों में है। दरअसल, खरगे ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना आतंकवादी से कर दी। उन्होंने तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एआईएडीएमके वाले पीएम मोदी से कैसे जुड़ सकते हैं। वे तो आतंकवादी हैं। खरगे की इस टिप्पणी के बाद के जब विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री एक आतंकवादी हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि वह लोगों और राजनीतिक दलों को डराने-धमकाने का काम करते हैं। खरगे ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा धमकियां देते हैं और उनके आचरण से राजनीतिक गलियारों में डर पैदा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाना था, न कि उन पर कोई व्यक्तिगत हमला करना।

महिला आरक्षण बिल

महिलाओं के लिए कोटा 2034 से पहले संभव हो पाएगा या फिर बीच की कोई और राह अभी भी निकल सकती है?

महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान भागीदारी कब?

सौरभ वार्ष्णेय

महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान भागीदारी देने के उद्देश्य से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। लेकिन यह सवाल स्वाभाविक है कि जब यह कानून संसद से पारित हो चुका है, तो इसका असर अभी तक ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं दिख रहा। दरअसल, इस अधिनियम के लागू होने में देरी का कारण इसकी संरचना और उससे जुड़ी शर्तें हैं। देश की संसद में 31वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया जो कि बहुत ही निराशाजनक है। संसद के विशेष सत्र में लंबी चली बहस में मतभेदों के सुर के आलावा आपसी राजनीति के आलावा कुछ समझ नहीं आया। ज्ञात रहे कि सरकार को इस संशोधन बिल को पास करवाने के लिए दो-तिहाई वोटों की जरूरत थी। लेकिन पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े। विरोध में 230 वोट पड़े, जो दो तिहाई से बहुत कम हैं। इस बिल को पास करवाने की नरेंद्र मोदी सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतरआत्मा की आवाज सुनने वाली अपील भी कुछ खास असर नहीं दिखा पाई। अब सवाल यह है कि अब नहीं तो महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण कब मिलेगा ? जब सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पास होकर उसका नोटिफिकेशन हो चुका है तो पहले आगामी चुनाव में इसे लागू कर देते और संशोधन बिल लाते रहते? जब इसे अभी लागू ही नहीं किया तो संशोधन बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी। महिलाओं के लिए कोटा 2034 से पहले संभव हो पाएगा या फिर बीच की कोई और राह अभी भी निकल सकती है? महिला आरक्षण बिल फिलहाल तो ठंडे बस्ते में चला गया है। ये कह पाना मुश्किल है कि बिल अब कब लागू हो पाएगा? जबकि यह अब कानून बन चुका है। इसे लागू करना हम सब सांसदों की जिम्मेदारी है।

विपक्ष लगातार ओबीसी महिलाओं के अलग कोटे की मांग कर रहा है। वह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी महिला आरक्षण का क्रेडिट तो लेना चाहती है लेकिन ओबीसी महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी देने से बच रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर फैसलों में कहा है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता और ओबीसी कोटा के लिए समकालीन, भरोसेमंद तथ्यात्मक डेटा ज़रूरी है। यही तर्क राष्ट्रीय स्तर पर भी उठेगा। संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर लोकसभा-विधानसभाओं में ओबीसी वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण और उसमें से ओबीसी महिलाओं का उप-कोटा तय कर सकती है। भले ही नई जातिगत जनगणना पूरी नहीं हुई हो। संविधान किसी विशेष डेटा स्रोत को अनिवार्य नहीं ठहराता। लेकिन किस जाति समूह को कितना हिस्सा मिलेगा, इसका आधार तय करने के लिए ठोस, नए और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य जातिगत आंकड़े जरूरी होंगे। वरना अदालतों में इसे मनमाना मानकर चुनौती दी जा सकती है। अब आगे महिलाओं को ही मुखर होकर आगे आना होगा । इन पार्टियों को समझाना पड़ेगा कि आधी आबादी को संसद से क्यों वचिंत रखना चाहते हैं।

अब बात करते हैं इसके बीच के रोडे कि जिसमें परिसीमन की शर्त यानी कानून के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी, सीटों की नई सीमाएं तय होने के बाद ही यह आरक्षण लागू होगा। चूंकि अगली जनगणना अभी बाकी है और उसके बाद परिसीमन होना है, इसलिए कानून तुरंत प्रभाव से लागू नहीं हो सकता।

दूसरा कारण जनगणना में देरी। 2021 की जनगणना विभिन्न कारणों से टल गई थी। जब तक नई जनगणना नहीं होती, तब तक परिसीमन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। यह देरी सीधे तौर पर महिला आरक्षण के लागू होने को भी टाल रही है। तीसरा कारणः राजनीतिक संतुलन और आशंकाएं यानी परिसीमन के साथ ही राज्यों के बीच सीटों का संतुलन भी बदल सकता है, जिससे खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में प्रतिनिधित्व घटने की आशंका जताई जा रही है।

माओवादी ताकत की पहचान थे हथियार, अब वही खात्मे के बन रहे हैं सबूत

जगदलपुर। बस्तर कभी माओवादी संगठन का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और अंदरूनी इलाके माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाने हुआ करते थे। यहीं से क्क्व बटालियन हथियारबंद कैडरों के दम पर बड़े हमलों को अंजाम देती थी। बंदूक, बारूद और अत्याधुनिक हथियारों के सहारे वर्षों तक दहशत कायम रखी गई। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। जिस हथियारों के दम पर माओवादी अपनी ताकत दिखाते थे, वही हथियार अब सुरक्षा बलों के कब्जे में पहुंच रहे हैं। लगातार हो रही रिकवरी यह संकेत दे रही है कि बस्तर में माओवादी नेटवर्क पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है। बस्तर में माओवाद खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की रणनीति अब केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि माओवादियों की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है। लगातार सर्चिंग अभियान, मुठभेड़ और अंदरूनी इलाकों में दबिश के दौरान बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए जा रहे हैं। कई मुठभेड़ों में जवानों ने्र्च-47, ढ्ढहृस्स्, स्ररुऔर अन्य अत्याधुनिक हथियार जब्त किए हैं। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली भी अपने साथ हथियार सौंप रहे हैं। इससे साफ है कि संगठन के भीतर मनोबल टूट रहा है, और हथियारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती जंगलों में छिपाए गए हथियारों के डंप को खोज निकालना भी है। माओवादी वर्षों से जमीन के भीतर, गुफाओं में और जंगलों के गुप्त ठिकानों में हथियार छिपाकर रखते थे। अब लगातार इन डंप स्थलों को खोजा जा रहा है। हर बरामद

बस्तर में लाल नेटवर्क की टूटने लगी कमर

हथियार केवल एक सामान नहीं, बल्कि माओवादी नेटवर्क के कमजोर होने का प्रमाण माना जा रहा है। सुरक्षा बलों का दावा है कि हथियारों की कमी संगठन की हमलावर क्षमता को सीधे प्रभावित कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश गठन के बाद से अब तक बस्तर में साढ़े तीन हजार से ज्यादा हथियार बरामद किए जा चुके हैं।

यह आंकड़ा बताता है कि वर्षों से कितनी बड़ी मात्रा में हथियार माओवादियों के पास जमा थे। साल 2020 में 89, 2021 में 80, 2022 में 61, 2023 में 35, 2024 में 286, 2025 में रिकॉर्ड 677 और साल 2026 में अब तक 316 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। यानी पिछले दो वर्षों में रिकवरी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो सुरक्षा बलों की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। माओवादियों के पास कभी एके 47, INSAS, SLR, LMG, BGL जैसे हथियार बड़ी संख्या में हुआ करते थे। इन हथियारों के दम पर घात लगाकर हमला, कैंप पर फायरिंग और बड़े एंबुश को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब लगातार रिकवरी और ऑपरेशन के बाद यह जखीरा लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुका है।

हथियारों की कमी माओवादी संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। सबसे ज्यादा करेगुट्टा ऑपरेशन चत्तस्न में नक्सलियों का आधुनिक हथियार मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बरामद किया गया था. उस वक्त से ही नक्सलियों का हौसला पूरी तरह टूट गया और मुख्यधारा में जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। जानकारों के मुताबिक, माओवादियों के पास मौजूद अधिकतर हथियार लूट, तस्करी और अवैध निर्माण के जरिए जुटाए गए थे। साल 2004 में उड़ीसा के कोरापुट शस्त्रागार लूटकांड से बड़ी मात्रा में हथियार हाथ लगे थे। वहीं बस्तर में कई बड़े हमलों के बाद शहीद जवानों से भी हथियार लूटे गए। 2007 का रानीबोदली हमला और 2010 का ताड़मेटला कांड इसके बड़े उदाहरण रहे।

इसके अलावा माओवादी अपनी फैक्ट्रियों में कट्टा, सिंगल शॉट गन और क्क्नर जैसे हथियार भी तैयार करते थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से तेलंगाना, महाराष्ट्र , आंध्रप्रदेश में नक्सली हथियारों को सरेंडर कर रहे हैं और नक्सलियों द्वारा लिए सभी हथियार लगभग वापस आ चुका है। यह पूरा तंत्र बिखरता नजर आ रहा है।

सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा सर्व शिक्षा अभियान समग्र के खाते से उड़ाए लाखों रुपए

■ **मरवाही जनपद में बड़ा घोटाला**

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जनपद पंचायत मरवाही में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट ने शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस खेल का खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान समग्र मद के खाते से लाखों रुपये का लेन-देन किया गया है। यह पूरा ट्रांजेक्शन सर्व शिक्षा अभियान समग्र के स्थापित नियमों के विपरीत है।? मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वर्तमान राज्य सरकार ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सभी विकासखंड स्रोत समन्वयक को स्पष्ट आदेश दिया था कि सर्व शिक्षा अभियान समग्र की राशि वापस की जाए। सरकार के इस सख्त निर्देश के बावजूद, मरवाही जनपद में राशि को वापस करने के बजाय उसे लगातार खर्च किया जाता रहा। नियमों के मुताबिक, इस खाते से किसी भी प्रकार का भुगतान बिना क्क्रष्ट की सहमति या उनके हस्ताक्षर के संभव नहीं है। ऐसे में बिना के संज्ञान या हस्ताक्षर के लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन होना जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली और मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, सर्व शिक्षा अभियान समग्र के बैंक खातों का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विकासखंड समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से होना अनिवार्य है। लेकिन मरवाही में इन नियमों को दरकिनार कर सीईओ जनपद द्वारा एकल या अनाधिकृत रूप से खातों का संचालन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक शाखा मरवाही के खाता क्रमांक 11556672537 के विवरण चौंकाने वाले हैं - 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024= इस अवधि के दौरान खाते से 99 लाख 27 हजार 684 रुपये अन्यत्र डेबिट किए गए। ?27 मई 2024 से 12 जून 2025 इस छोटी सी अवधि में भी 12 लाख 64 हजार 276 रुपये का आहरण किया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि राज्य शासन द्वारा इस योजना की शेष राशि को वापस करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाने के बाद भी, इस मद से लगातार पैसा निकाला जाता रहा। दस्तावेजों से यह भी संकेत मिले हैं कि सरकारी राशि का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान समग्र में खर्च तो नही किया, लेकिन पेट्रोल पंपों, टूर एंड ट्रेवल्स और कुछ व्यक्तिगत नामों के खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया गया। सवाल यह उठता है कि जिस राशि पर तत्कालीन और वर्तमान सीईओ का ट्रांजैक्शन अधिकार ही नहीं था, उसे निजी कार्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। इस पूरे गड़बड़झाले में तत्कालिक और वर्तमान सीईओ मरवाही की कार्यप्रणाली जांच के दायरे में है। नियमों के विरुद्ध इन ट्रांजैक्शनों ने प्रशासन की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ?संयुक्त खाते का नियम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्व शिक्षा अभियान समग्र का बैंक खाता कभी भी सिंगल ऑपरेटेड एकल संचालित नहीं होता। इसे क्क्रष्ट (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) और ष्टश्वह्र (जनपद पंचायत) के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही संचालित किया जाना चाहिए। इस अभियान के तहत राशि का आवंटन विशिष्ट कार्यों जैसे भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, या जल संचयन के लिए मद-वार (।द्गड्डस्र-2द्बह्यद्ग) किया जाता है। राज्य शासन और स्क्क्ह्र (राज्य परियोजना कार्यालय) के निर्देशों के अनुसार, अप्रयुक्त राशि को सरेंडर करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे। यदि अभी अब तक राशि जमा नहीं की गई है, तो इसकी भी जांच होगी।

मामले में जिला पंचायत ष्टश्वह्र मुकेश रावटे ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान समग्र और अन्य योजनाओं की राशि का व्यय नियमानुसार होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में से प्रतिवेदन मांगा जा रहा है।

किसानों के लिए वरदान बना देसी करहनी धान, औषधीय गुण के साथ देता है ज्यादा मुनाफा

■ **कोरिया जिले का देसी धान अब किसानों के लिए फायदे का सौदा बनते जा रहा है.कम लागत में ही करहनी धान अच्छा मुनाफा देता है**

कोरिया। बदलते मौसम, गिरते जलस्तर और खेती की बढ़ती लागत के बीच पारंपरिक धान की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनते जा रही है। इन सबके बीच कोरिया जिले का देसी करहनी धान अब किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। ये धान सिर्फ फसल नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक मजबूती और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य का आधार बनते जा रहा है। कम समय में तैयार होने वाला, कम पानी में अच्छी उपज देने वाला और औषधीय गुणों से भरपूर यह धान अब जिले के किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यही वजह है कि इसकी खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है और किसान इससे बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। कोरिया जिले के किसान लक्ष्मी नारायण राजवाड़े बताते हैं कि करहनी धान की खेती उनके परिवार में पीढ़ियों से होती आ रही है। उनके पिताजी और पूर्वज करीब कई सालों से इसकी खेती करते आ रहे हैं। जहां सामान्य धान को तैयार होने में 100 से 120 दिन लगते हैं, वहीं करहनी धान महज 90 से 100 दिनों में ही पककर तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, इसे देरी से बोने पर भी अच्छी उपज मिल जाती है, जो किसानों के लिए एक बड़ा फायदा है।खासतौर पर उन इलाकों में जहां मानसून अनिश्चित रहता है। इस धान की सबसे खास बात इसके औषधीय गुण हैं। किसान लक्ष्मी नारायण की पत्नी सुमित्रा राजवाड़े बताती हैं कि जो लोग इस चावल को खाते हैं, वे खुद आकर बताते हैं कि इससे शुगर और बीपी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।विशेषज्ञ भी इसकी पुष्टि करते हैं। करहनी धान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे जीआई टैग के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

राइस मिल के गोदाम में लगी भीषण आग

कांकेर। कांकेर जिले के कुलगांव में मंगलवार को अजीबी एग्रो राइस मिल में भीषण आग लग गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना में बड़ी मात्रा में बारदाना और धान को नुकसान पहुंचा है। पूरी घटना कोतवाली थाना इलाके की है। जानकारी के मुतबाकि, सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं मालिक मोहम्मद आवेश भी राइस मिल पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धान के बोरों में लगी भ्यावह आग का मंजर नजर आ रहा है।

राइस मिल मालिक मोहम्मद आवेश ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। चांवल, धान और खाली बोरे सभी कुछ जल गया है। नुकसान का अभी आकलन नहीं किया जा सकता है।

शराब दुकान कर्मचारियों पर आर्थिक संकट तीन माह से वेतन नहीं

कलेक्टर बोले-राज्य स्तर की समस्या

■ **धमतरी में 27 शराब दुकानों में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं.उनका कहना है कि सबसे ज्यादा राजस्व मिलने के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा.**

धमतरी। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के कर्मचारी इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लगातार वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी उधार लेकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, तो कुछ के सामने बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी बड़ी चुनौती बन गई है।

धमतरी जिले में कुल 27 शराब दुकानें संचालित हैं, जहां सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। वेतन भुगतान में हो रही देरी का सीधा असर इन सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस विभाग से शासन को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है वहीं के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना बेहद चिंताजनक है।

शराब दुकान कर्मचारी दुर्गेश सिन्हा ने बताया कि करीब 2 माह 21 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन से मांग है कि जहां से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है वहीं के कर्मचारियों को वेतन के लिए भुगतना पड़ रहा है।

वहीं कर्मचारी गीतेंद्र साहू ने कहा कि फरवरी और मार्च माह का वेतन अब तक नहीं मिला है और अप्रैल के 21 दिन भी गुजर चुके हैं, फिर भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। इस संबंध में अधिकारियों को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

इधर, इस पूरे मामले पर धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा का कहना है कि यह समस्या जिला स्तर की नहीं, बल्कि राज्य स्तर की है। शासन को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करा दिया गया है और जल्द समाधान होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे शातिर अपराधी को दबोचा

रायगढ़। जिले में लगातार हो रही उठाईगिरी, लूट और चोरी की वारदातों के बीच लैलूंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय शातिर आरोपी अरविंद प्रताप सिंह उर्फ अरविंद नट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले के भलगढ़ का रहने वाला है और अपने साथी ओमप्रकाश उर्फ बच्चा सिसोदिया के साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल उसका साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। थाना लैलूंगा क्षेत्र में जनवरी 2026 के दौरान बुधवारी बाजार, टीवीएस शोरूम और स्टेट बैंक शाखा के पास मोटरसाइकिल की डिक्की से लगातार उठाईगिरी की घटनाएं सामने आई थीं। मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसडीओपी धरमजयगढ़ और थाना प्रभारी को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अंतरराज्यीय इनपुट जुटाए।

94 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त, गिरफ्तार

महासमुंद। वनमंत्री केदार कश्यप की मंशानुसार वन क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध संचालित अभियान के अंतर्गत 20 अप्रैल को वनमंडल महासमुंद के बागबहरा परिक्षेत्र अंतर्गत आमाकोनी सर्किल, तमोरा बीट के कक्ष क्रमांक 95 एवं 96 (आरक्षित वन) में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम तमोरा के कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 94 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण करते हुए हरे-भरे एवं मूल्यवान वृक्षों की अवैध कटाई की गई तथा कृषि प्रयोजन हेतु भूमि पर अनधिकृत कब्जा स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापक खुदाई/जुताई की गई थी। साथ ही, वनभूमि की सीमा निर्धारण हेतु स्थापित सीमेंट-कांक्रीट निर्मित मुनारों (सीमा चिन्हों) को तोड़ा/क्षतिग्रस्त किया गया। इन अवैध गतिविधियों के परिणामस्वरूप मूल्यवान वृक्ष प्रजातियों एवं औषधीय जड़ी-बूटियों को भारी क्षति पहुँची है, जो कि पूर्णत: विधि-विरुद्ध एवं दंडनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम।

विद्युत दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों आर्थिक सहायता राशि प्रदान

बालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान विद्युत दुर्घटना के कारण मृत हो जाने वाले 02 व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इसके अंतर्गत उन्होंने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम ठेमाबुजुर्ग निवासी श्री हेमलाल चुरेन्द्र के विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ओमाबाई चुरेन्द्र को एवं रायपुरा निवासी समारू राम के विद्युत दुर्घटना में मृत होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेहतरीन बाई को 04-04 लाख रूपये का आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों के विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों के लिए 04-04 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, नूतन कंवर एवं अजय किशोर लकरा सहित छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता एसके बंड सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

40 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे से सुदृढ़ हुई शहर की सुरक्षा

सुकमा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के समन्वित प्रयासों से सुकमा शहर में मिशन सिक्योर सिटी सुकमा के अंतर्गत जिला कलेक्टर अमित कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण, के नेतृत्व में विशेष प्रयास से जिला मुख्यालय सुकमा में अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड सर्विलांस एवं कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इस उन्नत प्रणाली के अंतर्गत शहर के विभिन्न संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर कुल 40 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन जिला कंट्रोल रूम से सतत रूप से किया जा रहा है। इससे शहर की गतिविधियों पर 24म7 प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो रही है। जिला पुलिस प्रशासन सुकमा, नागरिकों के सहयोग से सुरक्षित, सशक्त एवं अपराध मुक्त सुकमा के निर्माण हेतु निरंतर प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है। एसपी सुकमा किरण चव्हाण ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम, तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

सीएम स्वस्थ बस्तर अभियान का लाभ उठाने की अपील

कोण्डागांव। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत मंगलवार को जिला कार्यालय में कोंड़ागांव कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की। यह अभियान स्वस्थ बस्तर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंच रही हैं। नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने और इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बस्तर संभाग में शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम परिवार के सभी सदस्यों की घर-घर जाकर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर रही है। इसके माध्यम से डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल भी बनाए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य मावा सेहत, मावा बस्तर' के अंतर्गत हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, कैंसर, टीबी, मलेरिया और कुष्ठ सहित अन्य मौसमी बीमारियों की नि:शुल्क जांच हो रही है।

सेक्टर 6 ए मार्केट में व्यापारियों का प्रदर्शन

■ **प्रीमियम शराब दुकान खोलने का विरोध, सेक्टर 6 ए मार्केट में व्यापारियों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी**

भिलाई। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 6 के ए मार्केट में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने के फैसले का स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। सोमवार को आबकारी विभाग ने जैसे ही दुकान शुरु की विरोध का माहौल बन गया। विरोध स्वरूप सेक्टर 6 मार्केट के व्यापारी, स्थानीय नागरिक और कांग्रेस के नेता समेत कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते दिखे।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेक्टर 6 ए मार्केट भिलाई का प्रमुख और सबसे व्यस्त बाजार है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में परिवार, महिलाएं और बच्चे खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे स्थान पर शराब दुकान खोलना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे शहर की सामाजिक छवि भी प्रभावित होगी।लोगों ने इस फैसले को भिलाई की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया है।बीएसपी द्वारा दुकान का आवंटन करना पूरी तरह गलत है। यह निर्णय बिना स्थानीय सहमति के लिया गया है।यदि शराब दुकान खोलनी ही है तो सिविक सेंटर जैसे स्थानों पर खोली जाए, लेकिन हर भीड़भाड़ वाले बाजार में इसे खोलना उचित नहीं है-राजेश चौधरी,आम जनता प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दुकान को कहीं और स्थानांतरित नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले खुर्सीपार गेट के पास मौजूद शराब दुकान को लेकर भी हंगामा हुआ था। शराब दुकान के कारण आए दिन मारपीट की घटनाएं होती थी। मारपीट के दौरान हत्या की वारदात के बाद शराब की दुकान को स्थानांतरित किया गया। अब एक बार फिर व्यस्ततम बाजार में शराब दुकान खोलने का विरोध हो रहा है।

हादसे के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं, डैम के बाहर बह रही राख

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का सबसे बड़े पावर प्लांट 1320 मेगावाट की क्षमता वाले एचटीपीएस संयंत्र के झाबू स्थित राखड़ डैम का तटबंध रविवार को टूट गया। जिससे 21 वर्ष के एक जेसीबी ऑपरेटर मड़वारानी निवासी हुलेश्वर कश्यप की मौत हो गई। युवक सैकड़ों टन राख के सैलाब में नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जहां की परिस्थितियां बेहद चौंकाने वाली थी।

रविवार के हादसे से पावर कंपनी ने कोई सीख नहीं ली है। मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। तटबंध की मरम्मत शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण राख युक्त पानी डैम के बाहर बहते हुए दिखा। मरम्मत का काम अभी शुरू नहीं किया गया है, जबकि पावर प्लांट का संचालन राज्य विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। ऊर्जा विभाग के मुखिया स्वयं सीएम विष्णुदेव साय हैं। राखड़ डैम किसी भी कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। बिजली उत्पादन के दौरान जो राख प्लांट से उत्सर्जित होती है, उसे बड़े पाइप लाइन के जरिए राख डैम तक भेजा जाता है और इस राख डैम को केंद्रीय पर्यावरण मानको, एनजीटी के निर्देश के तहत रखरखाव करना होता है। लेकिन इस हादसे ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की तैयारी और व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। राख डैम के रखरखाव में भर्राशाही बरती जा रही थी, गांव झाबू का यह तटबंध पहले भी टूट चुका है, जिसके लिए 15 अप्रैल को एक इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन बावजूद इसके राख डैम की ठोस मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण यह हादसा हुआ।

दूसरे दिन जो सबसे आपत्तिजनक स्थिति राखड़ डैम में देखने को मिली, वह है राख का डैम से बाहर बहकर प्रवाहित होना। पर्यावरण मानकों के अनुसार पावर प्लांट से राख बाहर नहीं जाना चाहिए। लो लाइन एरिया में भी अनुमति लेकर राख को डंप किया जाता है।

सामान्य तौर पर इसे राख डैम तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसका प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह हवा चलने के साथ ना तो उड़े ना तो राख युक्त पानी किसी जल स्त्रोत को प्रदूषित करे। रविवार को झाबू में तटबंध टूटने के बाद एक जेसीबी ऑपरेटर की जान गई, दूसरे दिन भी इसके रखरखाव और मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर राख डैम से राखयुक्त पानी डैम से बाहर प्रभावित हो रहा है। जो हसदेव नदी में जाकर समाहित हो रहा है।

बस्तर के लिए खुले वैश्विक द्वार, 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर

रायपुर। बस्तर की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (एनएच-130 सीडी) एक क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान कर लैंड-लॉक्ड क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करेगा।

वर्तमान में जगदलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के कठिन घाटों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 से 9 घंटे का समय लगता है। भारी वाहनों के लिए यह मार्ग न केवल थकाऊ है, बल्कि डीजल की खपत और मेंटेनेंस के लिहाज से भी खर्चीला है। नया कॉरिडोर इस यात्रा को मात्र 3.5 से 4 घंटे में समेट देगा। सीधा और घाट-मुक्त रास्ता होने के कारण वाहनों का परिचालन खर्च काफी कम हो जाएगा, जिससे परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (एनएच-130 सीडी) छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर और कोंडागांव जिलों से गुजर रहा है।

जगदलपुर मुख्यालय को इस कॉरिडोर से जोडने के लिए ओडिशा के नबरंगपुर का दासपुर इंटरचेंज महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। जगदलपुर का ट्रैफिक मात्र 50-60 किमी का सफर तय कर नबरंगपुर इंटरचेंज के माध्यम से रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो सकेगा, जिससे बस्तर सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ जाएगा।

इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बस्तर की अरेबिका कॉफी, जैविक इमली, महुआ उत्पाद और प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुँचाना सुगम होगा। कम लॉजिस्टिक लागत के कारण ये उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय किसानों, संग्रहकर्ताओं और शिल्पकारों को उनकी उपज का बेहतर अंतरराष्ट्रीय मूल्य मिल सकेगा। बस्तर, कांकेर और कोंडागांव जैसे आकांक्षी जिलों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं इन सुदूर क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।

इस राजमार्ग के माध्यम से बस्तर का कृषि उत्पाद और इस्पात सीधे रायपुर, दुर्ग-भिलाई और विशाखापट्टनम जैसे औद्योगिक केंद्रों से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी, प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर में हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह कॉरिडोर बस्तर में औद्योगिक विकास की एक नई लहर लाने के लिए तैयार है। बस्तर क्षेत्र लौह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। यह कॉरिडोर इन खनिजों को विशाखापत्तनम पोर्ट तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे निर्यात और व्यापार में भारी उछाल आएगा। कॉरिडोर के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।कनेक्टिविटी में सुधार होने से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आमद बढ़ेगी।

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकल गणेश, कुतुमसर गुफा और चित्रकोट-तीरथगढ़ जैसे जलप्रपातों तक पहुंच आसान होगी। इससे न केवल पर्यटन राजस्व बढ़ेगा, बल्कि आदिम संस्कृति और लोक कलाओं को भी वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी। कांकेर जिले के बासनवाही के मंझिनगढ़ पहाड़ी (केशकाल) को चीरकर 2.79 किमी लंबी छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन-ट्यूब टनल बनाई जा रही है। यह टनल उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव जोन से गुजरती है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वन्यजीवों का आवागमन बाधित न हो।

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा- महिला आरक्षण पर बीजेपी की नियत में खोट

रायपुर। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं होने के बाद देशभर में सियासी पारा हाई है। इस बीच कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपत्ति परिसीमन बिल को लेकर है। जिसपर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में महिला आरक्षण बिल को लेकर आज महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण को 543 सीटों पर तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जनगणना के परिसीमन कैसे किया जा सकता है। जनगणना के बाद ही परिसीमन विधेयक लाया जाना चाहिए। मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। वह महिला विरोधी रवैया अपना रही है। वहीं रायपुर में सोमवार को बिल गिराने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ते हुए भाजपा ने जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए। इसे आज प्रेसवार्ता में कांग्रेस सांसद ने छलावा करार दिया।

छत्तीसगढ़ में जारी होगा सीएम हेल्पलाइन नंबर, राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकेगा शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू होने जा रहा है। 24 घंटे सक्रिय रहने वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर राज्य का कोई भी व्यक्ति समस्या या फिर शिकायत कर सकेगा। अफसरों को इन समस्याओं का तय सीमा में निराकरण करना होगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी जशपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में दी। उन्होंने बताया की सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों या फिर समस्याओं के निराकरण के लिए समय निर्धारित होगा। अगर तय समय पर शिकायत या समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के लिए आहुत विशेष सत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसे लेकर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है।वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। मैने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। लोग बदलाव लाना चाहिए।

मोंगरा बैराज के कार्यों के लिए 2.90 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के विकासखण्ड-अंबागढ़ चौकी की मोंगरा बैराज के जलद्वारों के सुधार एपाक्सी व सिंथेटिक पेंटिंग एवं विद्युत यांत्रिकीय उपकरणों के नवीनीकरण कार्य के लिए दो करोड़ 90 लाख 14 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्यों को पूर्ण कराने मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।ते हैं, भाजपा की सरकार वहां जरूर बनेगी।

दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 6.58 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बीजापुर जिले की दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 6 करोड़ 58 लाख 7 हजार रूपए स्वीकृति किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में भैरमगढ़ के कोडोली तालाब क्रमांक-एक के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 91 लाख 34 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। इसी तरह से भैरमगढ़ के ही मिरतुर तालाब के जीर्णोद्धार एवं तीन नग व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 66 लाख 73 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सिंचाई योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

3 नाबालिग बच्चियों का बाल आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका ने कराया रेस्क्यू

रायपुर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा को बीरगांव क्षेत्र में स्थित एक ईंट भट्टी में बच्चों से बाल श्रम कराए जाने की सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने तत्काल निर्देश देकर एक संयुक्त टीम का गठन करवाया । रणनीति के तहत एक बार मौका निरीक्षण करते हुए दूसरी बार आज प्रात- लगभग 6 बजे गठित टीम को पुनः मौके पर भेजकर कार्रवाई करवाई गई, जहां तीन नाबालिग बच्चियां कार्य करते हुए पाई गईं। सभी बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम पाई। टीम द्वारा तत्काल बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वर्तमान में बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत उन्हें सुरक्षित वातावरण, शिक्षा एवं बेहतर जीवन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकरण में बाल श्रम निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी । इस कार्यवाही में जिला बाल संरक्षण इकाई से माधुरी शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी संजय निराला, सामाजिक कार्यकर्ता गोरखनाथ पटेल, श्रम निरीक्षक श्री पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता अभिमन्यु भरिया एवं विपिन ठाकुर राज्य समन्वयक एसोसिएशन फॉर वॉलंटियरी एक्शन एवं चाइल्डलाइन टीम के सदस्य शामिल रहे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा द्वारा स्पष्ट किया है कि बाल श्रम के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।

वर्ल्ड टेबल टेनिस डे समारोह में वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान

रायपुर। वर्ल्ड टेबल टेनिस डे (23 अप्रैल) के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ एवं राजधानी टेबल टेनिस संघ, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में कल सप्रे शाला टेबल टेनिस हॉल, रायपुर में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टेबल टेनिस के साथ-साथ अन्य खेलों में भी उत्कृष्ट योगदान देने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला (आईपीएस) थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष श्री शरद शुक्ला जी ने किया तथा विशेष अतिथि छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री किशोर जादवानी जी एवं पूर्व संरक्षक डॉ. भरत अग्रवाल जी थे। संघ के उपाध्यक्ष श्री विनय बैसवाडे भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रायपुर महानगर टेबल टेनिस संघ के सचिव श्री शकील साजिद ने किया। इस अवसर पर खिलाडयों को सम्मानित किया गय। वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान (टेबल टेनिस) = टेबल टेनिस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरिष्ठ खिलाडियों श्री सुरेश दुबे, श्री शैलेश गोलछा, श्री राजपाल बघेल, डॉ. अनिल एस. कोटस्थाने, श्री राजीव काले और डॉ. स्वाति बांठिया को सम्मान-पत्र, श्रीफल एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रथम बार अन्य खेलों के खिलाडियों का उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मान प्रथम बार इस वर्ष से अन्य तीन खेलों में भी उत्कृष्ट योगदान देने वाले वरिष्ठ खिलाडियों को सम्मानित करने की शुरुआत की गई। इसमें श्रीमती नीता डुमरे (हॉकी), श्रीमती कविता दीक्षित (बैडमिंटन) एवं राजेश सोमवंशी (वालीबाल) को भी सम्मान-पत्र, श्रीफल एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में रायपुर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव अनुराग दीक्षित, कराते की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुश्री हर्षा साहू, छत्तीसगढ़ वेटरंस टेबल टेनिस समिति के सचिव प्रेमराज जाचक, तकनीकी समिति के चेयरमैन अरविंद कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जोशी, विमल नायर, गिरिराज बागड़ी, प्रणय मजुमदार, सुश्री ईरा पंत, सुश्री गीता पंडित, सुश्री रेणुका सुब्बा, डा. मोहन सावंत, डा. आलोक शर्मा, डा. विजय खंडेलवाल, सुश्री प्रमिला ठाकुर, सुश्री दिव्या आमदे, श्री अरुण बावरिया, हरीश पांडे, राकेश यादव, तरुण राठोड, प्रवीण निरापुरे, कु. प्रिया चावड़ा, मो शफाक, एस वत्स, सुश्री प्रमिला देवांगन, चिरंजीत राय सहित संघ के अनेक पदाधिकारीगण, खिलाड़ीगण एवं अभिभावकगण उपस्थित थे।

अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेगा राशन दुकानों में अनाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी राशन दुकानों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। अब हितग्राहियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। नए आदेश के अनुसार दोपहर की तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा निर्धारित छुट्टियों के दिनों में दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पहले राशन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हो रही थीं, जिससे तेज धूप में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समय में बदलाव से अब लोगों को सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकानों को नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम साय होंगे मुख्य अतिथि

छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के सामूहिक कन्या विवाह समारोह में 51 जोड़े लेंगे फेरे

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन इस वर्ष पुन: नि:शुल्क सामूहिक कन्या विवाह समारोह आयोजित करने जा रहा है। रविवार, 3 मई को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के वीआईपी हाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बतौर मुख्य आतिथ्य मौजूद रहेंगे। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल एवं प्रांतीय महामंत्री संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्ष की सफलता के बाद इस वर्ष भी 51 जोड़ों का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर सियाराम अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजेश अग्रवाल मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, संपत अग्रवाल विधायक, सत्यनारायण शर्मा पूर्व मंत्री, मोतीलाल साहू विधायक, जयदेव सिंघल महेंद्र सेक्सरिया, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, बृजलाल गोयल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के संयोजक शोभा केडिया, गुंजा सुल्तानिया, रमेश अग्रवाल एवं जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक समरसता, एकता एवं सेवा भाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह कराना एवं उन्हें सहयोग प्रदान करना है ।यह आयोजन समाज के उन परिवारों के लिए एक सशक्त पहल है, जो अपनी बेटियों के विवाह को गरिमामय रूप से संपन्न करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रचार-प्रसार प्रभारी ज्योति अग्रवाल एवं डॉ. नेहा अग्रवाल ने बताया कि सभी जोड़ों का विधिवत सत्यापन किया जा रहा है, ताकि पात्र हितग्राहियों को ही लाभ मिल सके। रायपुर जिला अग्रवाल संगठन के अध्यक्ष हरिकेश पालीवाल जिला महिला संगठन की अध्यक्षा प्रियंका अग्रवाल एवं पंडाल एवं व्यवस्था प्रभारी संजीव अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में बेटियों को गृहस्थी के जरूरतों के हिसाब से लगभग 50000 रुपए की सामग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें स्टील की बड़ी वाली अलमारी, बड़ी सूटकेस, मिक्सर ग्राइंडर, पंखा, इलेक्ट्रिक आयरन, विवाह के सारे प्रकार के कपड़े, घड़ी, जेवर के अलावा गृहस्थी के रोजमर्रा के सामान शामिल होंगे। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील रामदास अग्रवाल ने बताया कि समाज सेवा और मानवीय मूल्यों की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत करते हुए, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा एक भव्य नि:शुल्क सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

महतारी वंदन योजना से मिली नई दिशा, प्रेम बाई ने गुपचुप ठेले से बढ़ाई आय

रायपुर। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। ग्रामीण अंचलों की महिलाएं इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं। सक्ती जिले के विकासखंड सक्ती अंतर्गत ग्राम भूरसीडीह की निवासी श्रीमती प्रेम बाई पटेल इसकी प्रेरक उदाहरण हैं। श्रीमती प्रेम बाई पटेल को योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता की अब तक 26वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। इस नियमित सहयोग ने उनके जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाया है। उन्होंने प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए गुपचुप (पानीपुरी) का ठेला शुरू किया, जिसे वे गांव-गांव घूमकर संचालित करती हैं। इस छोटे व्यवसाय से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है, जिससे उनका परिवार अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। श्रीमती प्रेम बाई इस आय से घर की आवश्यक जरूरतों—जैसे राशन एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री—की पूर्ति कर रही हैं। साथ ही वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी बचत कर पा रही हैं। वे बताती हैं कि पहले जहां आर्थिक परेशानियां थीं, वहीं अब उनके जीवन में स्थिरता आई है, आत्मविश्वास बढ़ा है और स्वावलंबन की भावना विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने और महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से यह योजना मार्च 2024 में प्रारंभ की गई थी। तब से अब तक प्रदेश की हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 26 किस्तों में कुल 16,881 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिला है।

मधुशाला बार में युवक ने किराना व्यापारी पर बीयर की बोतल से किया हमला

रायपुर। रायपुरा चौक स्थित मधुशाला बार में सोमवार देर रात कार सवार युवक ने बार में घुसकर किराना व्यापारी पर बीयर की बोतल से हमला कर दिया और धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस डीडीनगर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी तलाश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जामगांव निवासी किराना व्यापारी संदीप अग्रवाल 18 अप्रैल की रात अपने दोस्त अनिवेश प्रताप सिंह के साथ मधुशाला बार पहुंचे थे।

सत करीब 11:30 बजे दोनों बार के बाहर खड़े थे, तभी चंगोराभाठा निवासी हर्ष शुक्ला तेज रफ्तार कार से वहां पहुंचा और अचानक उनके सामने गाड़ी रोक दी। इस हरकत से घबराकर दोनों अंदर बार में चले गए। हर्ष शुक्ला भी उनके पीछे-पीछे बार के अंदर घुस आया और गाली-गलौज शुरू कर दी।

इसके बाद उसने फ्रिज से बीयर की बोतल निकाली और संदीप अग्रवाल के सिर पर जोरदार वार कर दिया। हमले में संदीप के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के दौरान अनिवेश प्रताप सिंह ने बीच-बचाव किया, जिससे विवाद और ज्यादा नहीं बढ़ा। हालांकि मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की जल्द पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके।

राजधानी में हिंदू संगठन ने लेंसकार्ट का चश्मा तोड़कर किया विरोध

शॉप के भीतर घुसकर कर्मचारियों को लगाया टीका

रायपुर। सोशल मीडिया से शुरू हुआ लेंसकार्ट विवाद की राजधानी रायपुर में भी एंट्री हो गई है। ड्रेस कोड के विरोध में धर्म जागरण समिति की सह संयोजिका भारती वैष्णव ने कार्यकर्ताओं के साथ लेंसकार्ट शोरूम पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और कर्मचारियों को नाम पूछने के बाद टीका लगाया। इस दौरान स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि अगर कोई कंपनी हिंदू विरोधी कृत्य करती है तो उसका विरोध किया जाएगा।

धर्म जागरण समिति की सह संयोजिका भारती वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि मालिक कहता है लेंसकार्ट में काम करने वाला कर्मचारी न तिलक, न कलेवा बांध सकता है और न ही जनेव धारण कर सकता है, लेकिन महिला अगर मुस्लिम धर्म की हैं तो उन्हें हिजाब धारण करने की स्वकृति है। इसका हम विरोध करते हैं। इस पूरे विवाद के बीच कंपनी पहले ही अपनी सफाई दे चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ङ्क' पर जारी बयान में कंपनी ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी है। साफ़-साफ़ और खुले तौर पर। पिछले कुछ दिनों में हमारे समुदाय और ग्राहकों ने अपनी बात रखी है और हमने उसे ध्यान से सुना है। आज हम अपने 'इन-स्टोर स्टाइल गाइड' को मानकीकृत (स्टैंडर्डाइज़) कर रहे हैं और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक रूप से साझा कर रहे हैं। कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से और बिना किसी दुविधा के हमारे टीम के सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले हर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक का स्वागत करती हैं—जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, पगड़ी और भी बहुत कुछ। इन्हें अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि हमारी पहचान के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। कंपनी ने यह भी कहा कि यदि किसी कर्मचारी या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए उसे खेद है। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में सभी नीतियां समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होंगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दूरभाष - 0788-2210876

(ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना)

दुर्ग, दिनांक 13.04.2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र "अ" में प्रतिशत दर पर दिनांक 28.04.2026 तक आमंत्रित की जाती है:-

निविदा अमंत्रण सू. क्र./सि.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	आमंत्रण
08/188834	कबीरधाम के कवर्धा शहर के अंतर्गत आंतारिक पहुंच मार्ग लं. 4.50 कि.मी, सुखताल से सारंगपुर मार्ग लं. 4.50 कि.मी, कुरुवा से कामनबोड मार्ग लं. 2.00 कि.मी, सुकतरा सिंघनगढ मार्ग लं. 4.00 से 6.00 कि.मी, खम्हरिया मुख्य मार्ग से पैलपार मार्ग लं. 1.00 कि.मी. गैदपुर से गातापार मार्ग लं. 3.20 कि.मी, कुल लं. 18.20 कि.मी. कार्य का नवीनीकरण	134.07	द्वितीय
09/188835	जिला कबीरधाम के कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग लं. कुल 38. 20 कि.मी. में 12/4 से 16/10, 22/2 से 31/10 तथा 32/2 से 39/2-18.35 कि.मी. नवीनीकरण कार्य	199.91	द्वितीय
10/188836	जिला कबीरधाम विकास खण्ड पंडरिया के नगर पंडरिया में गांधी चौक से मुख्य मार्ग के पेट्रोल पम्प तक (शहरी क्षेत्र भाग 30/8 से 31/8 एवं 32/6 से 33/2) आदर्श रोड रूप में 2.00 कि.मी. नवीनीकरण कार्य	65.13	चतुर्थ

टीप:-

1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें ।

जी-262700251/9

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मंडल दुर्ग

अमेरिका-ईरान तनाव, युद्ध नहीं, संवाद ही समाधान

कांतिलाल मांडोत

मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है, जहां से आगे का रास्ता या तो स्थिरता और कूटनीति की ओर जाता है या फिर टकराव, अस्थिरता और वैश्विक संकट की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब एक बार फिर निर्णायक चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। खबरें हैं कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे को लेकर नई वार्ता का दौर इस्लामाबाद में शुरू हो सकता है। यह पूरा विवाद केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और यहां तक कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक, इस तनाव का असर गहराई से जुड़ा हुआ है। खासकर जब बात परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम की आती है, तो यह केवल रणनीतिक ताकत का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करेगा। यह बयान केवल एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं, बल्कि संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत भी माना जा रहा है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि यदि तय समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो मौजूदा संघर्ष विराम समाप्त हो सकता है और हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर, ईरान का रुख भी कम सख्त नहीं है। वह अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इसे शक की नजर से देखते हैं। यही अविश्वास इस पूरे विवाद की जड़ है, जिसने वर्षों से समाधान को मुश्किल बना रखा है। इस तनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का खतरा सीधे तौर पर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करता है। हाल ही में इस क्षेत्र में अस्थिरता के कारण कई जहाजों ने अपने रास्ते बदल दिए या यात्रा टाल दी, जिससे बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई। यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प और महत्वपूर्ण दोनों है। पाकिस्तान ने एक मध्यस्थ के रूप में दोनों पक्षों को बातचीत के लिए एक मंच देने की कोशिश की है। इस्लामाबाद में संभावित वार्ता इसी प्रयास का हिस्सा है। हालांकि, मध्यस्थता आसान नहीं होती, खासकर तब जब दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास हो और उनके हित एक-दूसरे के विपरीत हों। फिर भी, कूटनीति का यही उद्देश्य होता है कि संवाद के माध्यम से ऐसे समाधान खोजे जाएं जो सभी के लिए स्वीकार्य हों। इतिहास गवाह है कि जब-जब बातचीत के रास्ते बंद हुए हैं, तब-तब संघर्ष ने जन्म लिया है और उसका खामियाजा केवल संबंधित देशों ने ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने भुगता है। युद्ध कभी भी स्थायी समाधान नहीं देता। यह केवल विनाश, अस्थिरता और मानवीय संकट को जन्म देता है। आज के वैश्विक परिदृश्य में, जहां अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता अत्यधिक है, किसी भी बड़े संघर्ष का प्रभाव दूरगामी और गंभीर हो सकता है। इस पूरे विवाद का एक और पहलू यह है कि यह केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण से निकलेगी सत्ता की राह!

प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इनमें खासकर उत्तर बंगाल की 54 सीटें सबसे अहम मानी जा रही हैं। इनके नतीजों से ही तय होगा कि इस बार बंगाल में जीत का सेहरा किसके माथे पर बंधेगा। उत्तर बंगाल में यह चुनाव चाय बागान मजदूरों के अलावा कोच-राजबंशी और कामतापुरी तबके की पहचान की लड़ाई के तौर पर उभरा है। साथ ही इसके नतीजे दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में दशकों पुरानी गोरखा समस्या के राजनीतिक समाधान का रास्ता भी खोल सकते हैं।

खास तौर पर भाजपा के लिए मतदान का पहला दौर बेहद अहम है। वर्ष 2021 में उसने जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी। अब उसके सामने पहले दौर में उन सीटों पर कब्जा करने या उसे बढ़ाने की गंभीर चुनौती है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों के नतीजे राज्य में सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाती रहे हैं। इस इलाके के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर जिलों में फैले आठ सौ से ज्यादा चाय बागानों के करीब 15 लाख मजदूर इलाके की कम से कम 35 सीटों पर निर्णायक हैं।यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इन मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक देने और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने जैसे वादों के साथ लुभाने की कोशिश कर रही है।

राज्य का चाय उद्योग लंबे अरसे से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। कई बागान बरसों से बंद पड़े हैं। अब बागान मजदूरों की नई पीढ़ी पारंपरिक पेशे को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर नए-नए पेशे आअपना रही है। इलाके के चाय बागान मजदूर कुछ साल के अंतराल पर पाला बदलते रहे हैं। यह लोग रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के समर्थन का फैसला करते रहे हैं।

ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होने की वजह से लंबे समय तक यह इलाके वाममोर्चा का गढ़ रहे थे। लेकिन 2011 के बाद यहां मजदूरों का रुझान बदला और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उतरने लगे। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में में तृणमूल कांग्रेस ने इलाके की 54 में से 28 सीटें जीती थी। वर्ष 2016 में भी इलाके में पार्टी

का दबदबा कायम रहा। लेकिन वर्ष 2019 में तस्वीर तेजी से बदली। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इलाके की आठ में से सात लोकसभा सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य के बाकी हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बावजूद उसने 30 सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम रखा था। उस साल तृणमूल को 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोकसभा की आठ में से छह सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था। कूचबिहार सूट उसके हाथ से निकल गई थी। इलाके के राजबंशी और कामतापुरी तबके कम से कम 10 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। राजबंशी समुदाय की गिनती राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर होती है। कूचबिहार और आसपास के इलाके में बसे कामतापुरी समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए लंबे समय से अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। और इस मांग में हिंसक आंदोलन भी होते रहे हैं।

अब भाजपा ने उनकी समस्या के राजनीतिक समाधान का भरोसा दिया है। पार्टी ने राजबंसी और कामतापुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात कही है। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा उत्तर बंगाल को बंगाल से काटने की साजिश रच रही है। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में भाजपा और तृणमूल अपने स्थानीय सहयोग पर निर्भर हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पर्वतीय इलाके की तीनों सीटें अनित थापा के नेतृत्व वाली भारतीय जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। दूसरी ओर, भाजपा विमल गुरुंग के नेतृत्व वाली गोरखा मुक्ति मोर्चा के सहयोग से मैदान में है।

कभी अलग गोरखालैंड की मांग में सुर्खियां बटोरने वाले दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अब इस आंदोलन की गूंज नहीं सुनाई देती। इस मांग में आंदोलन करने वाली स्थानीय पार्टियां भी कई गुटों में बंट चुकी हैं। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखालैंड की समस्या के राजनीतिक समाधान का भरोसा दिया है। वर्ष 2021 में इलाके की तीनों सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार ही विजयी रहे थे।

जहां तक मुद्दों का सवाल है एसआईआर के तहत मतदाता सूची से कटे नाम के अलावा चाय उद्योग की मुश्किलें, मजदूरों की बदहाली और न्यूनतम मजदूरी के अलावा उत्तर बंगाल का विकास, राजबंशी और कर्मचारी के अलावा गोरखा समुदाय की पहचान और उनकी मांगों के राजनीतिक समाधान का मुद्दा ही इस बार चुनाव में छाया हुआ है। अब इनमें परिसीमन का मुद्दा भी जुड़ गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिसीमन के प्रमुख बनाते हुए अपनी रैलियों में कह रही हैं कि लोकसभा में इससे संबंधित बिल पास होने पर बंगाल का विभाजन तय था और दार्जिलिंग समेत उत्तर बंगाल के कई जिलों का अस्तित्व खत्म हो सकता था।

उत्तर बंगाल में कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां हार-जीत का फैसला बहुत कम अंतर से होता रहा है। एसआईआर के बाद चुनावी समीकरण बिगड़ने और बागान मजदूरों का रुझान बदलने के ट्रैक रिकार्ड के कारण इस बार उन सीटों को लेकर सत्ता के दावेदारों की चिंता बढ़ गई है।एकाध फीसदी वोट इधर-उधर होने की स्थिति में भी इनके नतीजे बदल सकते हैं। देश में मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जिले मुर्शिदाबाद और उससे सटे मालदा में भी पहले चरण में ही मतदान होना है। वर्ष 2021 में मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और दो भाजपा ने। लेकिन एसआईआर के कारण जिले में साढ़े चार लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटने से तृणमूल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मालदा जिले के 12 में से पिछली बार आठ सीटें तृणमूल को मिली थी और चार भाजपा को। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था। एसआईआर के कारण करीब 2 l40 लाख वोटरों के नाम कटने की वजह से इस बार भाजपा को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और कांग्रेस को खाता खुलने की।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के परिवार के असर वाले पूर्वी मेदिनीपुर के साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर में भी इसी दौर में मतदान होना है। इनमें वो नंदीग्राम सीट भी शामिल है जिस पर पिछली बार शुभेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया था।

परिसीमन के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक प्रचार की काट के लिए अब भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वह तृणमूल कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं तो पहले से ही सुरक्षित नहीं थी। अब संसद में बिल का विरोध कर तृणमूल कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में भाजपा पर बंगाल के विभाजन की साजिश रचने के आरोप लगा रही हैं। लेकिन भाजपा अपने प्रचार में इस बात पर जोर दे रही कि बदली हुई जमीनी परिस्थितियों में परिसीमन से कई पुराने मुद्दों का समाधान किया जा सकता था। यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि उत्तर बंगाल में गोरखा के अलावा कोच-राजबंशी और कामतापुरी समुदाय के लोग लंबे अरसे से पहचान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेता उत्तर बंगाल की अपनी रैलियों में इस समस्या के राजनीतिक समाधान का भरोसा देते रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भौगोलिक और जागितगतच विविधता को ध्यान में रखते हुए मतदान का पहला चरण सत्ता के दोनों दावेदारों यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए बेहद अहम है। खासकर भाजपा इस दौर में अपनी पिछली सीटों पर कब्जा कायम रखने के साथ ही उसे और बढ़ाने की कोशिश करेगी जबकि तृणमूल कांग्रेस उत्तर बंगाल में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा कर इलाके में अपने कमजोर होती पकड़ को दोबारा मजबूत करने का प्रयास करेगी।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यद्यपि भोगयोनि एवं दिव्य शरीरी होने के कारण इन्द्र को किसी प्रकार की भी हत्या का पाप नहीं लग सकता जैसा कि हम विश्वरूप आख्यान के प्रसङ्ग में पीछे लिख आये हैं, तथापि इन्द्रदेव मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले समस्त यज्ञों के मुख्य देवता हैं, अत: उन्हें मानव मर्यादा की भी भली प्रकार रक्षा करनी अभीष्ट थी इसलिये यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:- सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने स्वयं भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा उक्त हत्या का प्रायश्चित्त किया । धर्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि किसी भी पाप का यथावत् प्रायश्चित्त कर देने के बाद प्रायश्चित्ती प्राणी सर्वया विशुद्ध हो जाता है। तदनुसार इन्द्रदेव पर भी किसी प्रकार का आक्षेप शेष नहीं रहता। अत: देवराज इन्द्र का यह कार्य सर्वथा धर्मसंगत है ।

इसके अतिरिक्त मूर्तिमत्ती ब्रह्म-हत्या का उल्लेख भी केवल पुराणों में ही नहीं है, वह तो वेदों में भी तथैव अङ्कित है। पुराण ने जहां उसे बूढ़ी चाण्डालिनी से उपमित किया है, वहाँ वेदों में तो सर्वथा लोकोत्तर (= आठ पांव, चार आँख आदि आदि बताकर) शैतान का चर्खा ही बना छोड़ा है। अत: श्राप जो समाधान वैदिक-स्वरूप का कीजियेगा वही पौराणिक का भी समझ लीजियेगा ।

भ्रूण-हत्या का उद्योग

इन्द्र के चरित्र पर एक यह भी आक्षेप किया जाया करता है कि- उसने दिति के पेट में घुस कर वज्र * द्वारा उसके गर्भ को विदीर्ण कर डाला, परन्तु उनञ्झास टुकड़े कर डालने पर भी वह जीवित ही रहा। अन्त में दिति से एक के बजाय 46 जीवित बच्चे पैदा हुये, जो मरुत् नामक देवता कहे जाते हैं। यह चरित्र गर्भपातन रूप अधर्म से परिपूर्ण, एवं सृष्टिनियम के प्रतिकूल किसी के पेट में घुस जाना आदि असम्भव वातों का भण्डार है। हम क्रमागत शैली के अनुसार इसका विवेचन करते हैं।

क्रमशः ..

विश्व पृथ्वी दिवस

योगेश कुमार गोयल

न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी तथा मौसम का निरन्तर बिगड़ता मिजाज गंभीर चिंता का सबब बना है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विगत वर्षों में दुनियाभर में दोहा, कोपेनहेगन, कानकुन इत्यादि बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद इस दिशा में अभी तक ठोस कदम उठते नहीं देखे गए हैं। दरअसल वास्तविकता यही है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रकृति के बिगड़ते मिजाज को लेकर चर्चाएं और चिंताएं तो बहुत होती हैं, तरह-तरह के संकल्प भी दोहराये जाते हैं किन्तु सुख-संसाधनों की अंधी चाहत, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और

रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के दबाव के चलते इस तरह की चर्चाएं और चिंताएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदान करने तथा पृथ्वी को बचाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को 'विश्व पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है।

प्रकृति पिछले कुछ समय से बार-बार भयानक आंधियों, तूफान और ओलावृष्टि के रूप में यह गंभीर संकेत देती रही है कि विकास के नाम पर हम प्रकृति से भयानक तरीके से जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप मौसम का मिजाज कब कहां किस कदर बदल जाए, कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनियाभर में मौसम का मिजाज किस कदर बदल रहा है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव के तापमान में एक-दो नहीं बल्कि करीब 30 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई।

मौसम की प्रतिकूलता साल दर साल किस कदर बढ़ती जा रही है, यह इसी से समझा जा सकता है कि कहीं भयानक सूखा तो कहीं बेमौसम अत्यधिक वर्षा, कहीं जबरदस्त बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड, कभी-कभार ठंड में गर्मी का अहसास तो कहीं तूफान और कहीं भयानक प्राकृतिक आपदाएं, ये सब प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ के ही दुष्परिणाम हैं और हमें यह सचेत करने के लिए पर्याप्त हैं कि अगर हम इसी प्रकार प्रकृति के संसाधनों का बुरे तरीके से दोहन करते रहे तो हमारे भविष्य की तस्वीर कैसी होने वाली है।

हालांकि प्रकृति कभी समुद्री तूफान तो कभी भूकम्प, कभी सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखाकर हमें चेतावनी भी देती रही है किन्तु जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर वैश्विक चिंता व्यक्त करने से आगे हम शायद कुछ करना ही नहीं चाहते। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार हम यह समझना ही नहीं चाहते कि पहाड़ों का सीना चीरकर हरे-भरे जंगलों को तबाह कर हम जो कंक्रीट के जंगल विकसित कर रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर हम अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पहाड़ों में बढ़ती गर्माहट के चलते हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं।

होर्मुज की उथल-पुथल के बीच मोदी से मिले कोरियाई राष्ट्रपति

अभिनय आकाश

चीन ने भारत के खिलाफ अग्रेसिव रुख लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज के नाम बदल दिए थे। उसके बाद भारत ने एक डिप्लोमेसी अपनाई थी जिसके तहत भारत ने भी चीन के कुछ एरियाज के नाम बदले थे। अमेरिका के नजदीक जैसे-जैसे भारत जाने लगा तो चीन से दूरियां हमारी बढ़ना लाजमी है। अब भारत ने चीन के अगेंस्ट एक ऐसा कदम लिया है जो कि डिप्लोमेटिकली उसे वर्ल्ड ऑर्डर में चीन से बहुत आगे रख देगा। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे जाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को भारत में इनवाइट किया। वो 19 से लेकर 21 तारीख तक तीन दिन की राष्ट्रीय विजिट पर भारत में आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ बेहद अहम बैठक हुई। लगभग एक दशक तक, नई दिल्ली (भारत) और सियोल (दक्षिण कोरिया) के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा कागज़ों पर ही नज़र आई। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा, लेकिन 2018 में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन की यात्रा के दौरान जो राजनीतिक उत्साह दिखा था, वह धीरे-धीरे फीका पड़ गया। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते कभी टूटे नहीं थे, लेकिन दोनों देशों की अपनी-अपनी तात्कालिक रणनीतिक मजबूरियों के कारण ये अक्सर पीछे छूट गए। दक्षिण कोरिया मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के मुद्दों, अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को संभालने और चीन पर अपनी भारी आर्थिक निर्भरता में उलझा रहा। इसके अलावा, वहाँ की बदलती घरेलू राजनीति और राष्ट्रपति के लिए केवल एक कार्यकाल वाले सिस्टम ने लंबी अवधि की रणनीतियों को बनाए रखना मुश्किल कर दिया। वहीं दूसरी ओर, भारत हिमालयी सीमा पर चीन के साथ तनाव को संभालने, पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं और अन्य बड़ी महाशक्तियों के साथ अपने

कूटनीतिक एजेंडे में व्यस्त था।

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच एक अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बातचीत के दौरान मुख्य फोकस वैश्विक स्तर पर मची उथल-पुथल—खासकर ईरान और इज़राइल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष—पर ही रहा। दोनों नेताओं ने इस बात पर गहराई से विचार-विमर्श किया कि युद्ध और तनाव के इस मौजूदा दौर में भारत और दक्षिण कोरिया अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और अधिक मज़बूत कैसे बना सकते हैं। बैठक के बाद, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता का संदेश देते हुए दोनों नेताओं ने मिलकर एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी इस महत्वपूर्ण मुलाकात की झलकियां साझा की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हज़ारों सालों पुराना सांस्कृतिक जुड़ाव है। उन्होंने याद दिलाया कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरियाई राजा किम-सुरो के बीच हुआ विवाह हमारी साझा और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आधुनिक दौर में भी यह जुड़ाव कायम है—जहाँ एक तरफ भारत में के-पॉप (K-Pop) और के-ड्रामा (K-Drama) की दीवानगी तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के लोग भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति को खूब पसंद कर रहे हैं।

दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) रहा है। 2009 में साइन किया गया और 2010 में लागू हुआ यह समझौता अब काफी पुराना माना जाता है। भारत अक्सर दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर करता रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को 50 अरब तक पहुँचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। क्या यह दौरा इस लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी %ऑक्सीजन% दे पाएगा? अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना ??है कि इसके लिए राजनीतिक दबाव तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद बारीकी से काम को अंजाम देना भी उतना ही ज़रूरी है। यह दौरा राजनीतिक दबाव तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ़ अपने दम पर नहीं। ऊँचे स्तर के दौरे इसलिए मायने रखते हैं, क्योंकि वे निवेशकों की अनिश्चितता को कम करते हैं। सरकारी अधिकारियों की गंभीरता का संकेत देते हैं और इंडस्ट्री को सिर्फ़ बातचीत से आगे बढ़कर काम को अंजाम देने के लिए बढ़ावा देते हैं। अगर दोनों नेता इस दौरे का इस्तेमाल सीईपीए से जुड़ी रुकावटों को दूर करने, समय-सीमा तय करने और कुछ खास क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करते हैं, तो 2030 तक 50 अरब का लक्ष्य ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा यह मुख्य लक्ष्य नहीं है; असली परीक्षा यह है कि क्या दोनों पक्ष अपने व्यापारिक संबंधों को ज़्यादा संतुलित, व्यापक और कुछ चुनिंदा निर्मित वस्तुओं पर कम निर्भर बना पाते हैं।

हालाँकि, 2018 की तुलना में 2026 के हालात पूरी तरह से अलग हैं। महामारी के बाद की दुनिया और अर्थव्यवस्थाओं द्वारा जोखिम कम करने की नीतियों ने दक्षिण कोरिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। एशिया अब केवल विकास की उम्मीदों पर नहीं चल रहा है। अब यह सप्लाई-चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की असुरक्षा, समुद्री विवादों, तकनीकी होड़ और उत्पादन के लिए केवल चीन पर निर्भर न रहने के दबाव से तय हो रहा है। इसके अलावा भारत अपने बड़े बाज़ार, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, डिजिटल विस्तार और %ग्लोबल साउथ% (विकासशील देशों) में अपने कूटनीतिक प्रभाव के कारण इन नई रणनीतियों के बिल्कुल केंद्र में आ गया है। वहीं दक्षिण कोरिया का मौजूदा नेतृत्व भी अब अमेरिका और चीन के बाज़ारों पर अपनी पुरानी निर्भरता से आगे देख रहा है। यही कारण है कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली की यह ताज़ा यात्रा अब केवल प्रतीकात्मक (दिखावे की) नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम मानी जा रही है।

राष्ट्रपति ली के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया दुनिया में अपनी एक नई और बड़ी पहचान बनाने की रणनीति पर तेज़ी से काम कर रहा है। इसका एक बहुत अहम हिस्सा ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना है। 2023 में भारत की ज20 अध्यक्षता के बाद से, %ग्लोबल साउथ% शब्द एक तरह से भारत के मज़बूत नेतृत्व की पहचान बन चुका है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग-राक ने हाल ही में बताया था कि उनकी इस रणनीति को आगे बढ़ाने में भारत की यात्रा एक मुख्य स्तंभ है। विकासशील देशों के बीच अपनी कूटनीति बढ़ाने में भारत, दक्षिण कोरिया की बहुत मदद कर सकता है। भारत की विकासशील दुनिया में जो गहरी पकड़, सम्मान और राजनीतिक वैधता है, वह दक्षिण कोरिया के पास अभी उस स्तर पर नहीं है। भारत को अब केवल एक एशियाई ताकत के तौर पर नहीं देखा जाता। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो अफ्रीका, हिंद महासागर के देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका (दक्षिण अमेरिका) के देशों के साथ सीधे जुड़ सकता है। भारत इन देशों के साथ विकास, उनकी क्षमता बढ़ाने और आज़ाद रणनीतिक सोच के मुद्दों पर उनकी ही भाषा में बात कर सकता है। दक्षिण कोरिया अब तक मुख्य रूप से अपने पुराने गठबंधनों और केवल अमीर देशों के बाज़ारों तक ही सीमित रहा है। अब जब वह अपनी कूटनीतिक और व्यापारिक पहुँच को दुनिया के अन्य हिस्सों में बढ़ाना चाहता है, तो भारत उसके लिए एक बेहद मूल्यवान और ज़रूरी साथी बन जाता है।

आज का इतिहास

1931 मिस्र और इराक के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
1954 तत्कालीन सोवियत रूस यूनेस्को में शामिल हुआ।
1967 यूएसएसआर में मार्शल लॉ लागू किया गया था।
1969 प्रथम मानव नेत्र प्रत्यारोपित किया गया।
1969 ब्रिटिश यॉट्समैन सर रॉबिन नॉक्स-जॉन्सटन ने दुनिया का पहला सोलो नॉन-स्टॉप सर्क्युमिनेशनऑफ पूरा करने के लिए संडे टाइम्सगोल्डन ग्लोब रेस जीती।
1970 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पृथ्वी दिवस आयोजित किया गया था।
1977 ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया।
1983 अंतरिक्ष यान सोयूज टी-8 पृथ्वी पर लौटा।
1983 श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट कैंडी में शुरू हुआ था।
1983 वेस्ट जर्मन समाचार पत्रिका स्टर्न ने एडॉल्फ हिटलर की डायरी के रूप में प्रकाशित किए गए अंश प्रकाशित किए, जो कि वर्सुबेरेटरी के सामने प्रकट हुए थे।
1991 अल्बानिया की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई।
1992 मेक्सिको में सीवर गैस विस्फोट में करीब 200 लोगों की मौत।
1992 कैलिफोर्निया 6.0 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से मारा गया था।
1992 गैस विस्फोट के कारण मेक्सिको में 200 लोग मारे गए थे।
1994 दुनिया का सबसे बड़ा लॉलीपॉप, जिसका वजन डेनमार्क में 3.011 पाउंड था।
1997 हौशे खेमिसी नरसंहार: अल्जीरिया में 93 ग्रामीण मारे गए।
1998 फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज़्नी वर्ल्ड रिज़ॉर्ट में डिज़्नी के एनिमल किंगडम को खोला गया, जिसमें 500 एकड़ (2 किमी 2) से अधिक को कवर किया गया, जिससे यह दुनिया का सबसे अकेला डिज्नी थीम पार्क बन गया।
2000 एक पूर्ववर्ती छापे में, यूएस इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइज़ेशन सर्विस एजेंटों ने मियामी, फ्लोरिडा में अपने रिश्तेदारों के घर से छह वर्षीय एलियन गोंजालेज को जब्त कर लिया और उसे अपने क्यूबा के पिता को लौटा दिया।
2004 उत्तर कोरिया के रयोंगचोन के योंगचेन स्टेशन पर ज्वलनशील कार्गो में विस्फोट हो गया, जिसमें 160 लोग मारे गए।
2005 बांडुंग (इंडोनेशिया) में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन आरम्भ।
2008 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हर बार विपक्ष, विरोध का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है

अद्वैता काला

बीते 17 अप्रैल को कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को खारिज कर दिया। यह वह विधेयक था, जिसके माध्यम से संविधान में पहले से ही दर्ज महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाना था। विधेयक पर हुए मतदान में 298 वोट पक्ष में और 230 वोट विपक्ष में पड़े, जबकि किसी भी सांविधानिक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इस विधेयक को आवश्यक बहुमत (352 मतों) से 54 वोट कम मिले। विपक्षी प्रवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि उन्होंने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं किया था, बल्कि परिसीमन के खिलाफ वोट दिया था। 2011 की जनगणना को आधार बनाने, ओबीसी उप-कोटा न होने और संघीय असंतुलन के खिलाफ वोट दिया।

यह कोई नई बात नहीं है। 1996 से लेकर अब तक, महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ी हर संसदीय चर्चा की यह लगातार नियति रही है। जिन नौ मौकों पर यह विधेयक पेश किया गया, उन सभी मौकों पर उस समय के विपक्ष ने विरोध करने का कोई ऐसा कारण ढूंढ निकाला, जो तकनीकी रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध नहीं था। देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48 प्रतिशत है। 18वीं लोकसभा में 543 सीटों में से 74 सीटें महिलाओं के पास हैं। यह 13.63 प्रतिशत है, जो 2019 के 14.36 प्रतिशत से कम है। 1952 से अब तक हुए आम चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। इसी रफ्तार से चले, तो महिलाओं को 22वीं सदी में जाकर बराबरी हासिल होगी।

अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ (आईपीयू) ने 185 देशों में से भारत को 143वें स्थान पर रखा है। वैश्विक औसत 26.9 प्रतिशत है, जो भारत के आंकड़े से लगभग दोगुना है। राज्य विधानसभाओं की स्थिति तो और भी खराब है। राष्ट्रीय औसत लगभग नौ प्रतिशत है। 2023 में, छत्तीसगढ़ 15 प्रतिशत का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना। 2024 में, केवल 9.7 प्रतिशत महिला उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाईं। 17वीं लोकसभा की वित्त समिति में 31 सदस्य थे, और उनमें से एक भी महिला नहीं थी।

महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ आपत्तियां भी उतनी ही पुरानी और चर्चित हैं। 1996 में देवगौड़ा सरकार थी, उस समय आपत्ति दर्ज की गई कि विधेयक में ओबीसी/मुस्लिमों के लिए कोई उप-कोटा नहीं है। समाजवादी पार्टी के शरद यादव,

राजद के लालू यादव और नीतीश कुमार ने यह आपत्ति दर्ज की। नतीजतन, विधेयक खत्म हो गया। 1998 में वाजपेयी सरकार में भी यही आपत्ति दर्ज की गई। उस समय राजग में शामिल रेल मंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के भीतर से ही इस विधेयक का विरोध किया। नतीजतन, इसे रोक दिया गया। वाजपेयी सरकार ने चार बार और (1999, 2001, 2002, 2003 में) प्रयास किया। वही आपत्ति, वही नतीजा।

2008-2010 में यूपीए सरकार थी। यह विधेयक नौ मार्च, 2010 को राज्यसभा में 186-1 वोटों से पारित हो गया था। सपा और राजद के हंगामे के बावजूद, भाजपा और वाम दलों के समर्थन की वजह से यह संभव हो पाया। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए, जिसके पास लोकसभा में बहुमत था, उसने इस बिल को कभी भी मतदान के लिए लोकसभा में पेश नहीं किया। नतीजतन, 2014 में यह विधेयक खत्म हो गया। जिस विधेयक को कांग्रेस अब राजीव गांधी का 'सपना' बता रही है, उसे लागू करने का जब उसके पास एकमात्र मौका था, तब उसकी अपनी ही सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

सितंबर 2023 में, मोदी सरकार ने 106वां संशोधन पेश किया। इतिहास में यह वह पल है, जिसे सर्वसम्मत माना जाता है। यह विधेयक लोकसभा में 454-2 और राज्यसभा में 215-0 से पारित हुआ। इस पर सबका नजरिया एकमत था। लेकिन बहस का रिकॉर्ड ऐसा नहीं था। भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है। तो फिर, 2023 की सर्वसम्मति का क्या, जब राजनीतिक सहमति बनी थी? असल में कैमरों के लिए 'हां' कहा गया था। वे आपत्तियां, जो बाद में अगली 'ना' को सही ठहराने का आधार बनतीं, पहले से ही रिकॉर्ड में दर्ज की जा रही थीं।

17 अप्रैल, 2026 को 2023 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य से लाया गया 131वां संशोधन विधेयक गिर गया। इस बार आपत्तियां थीं- परिसीमन, 2011 की जनगणना, ओबीसी उप-कोटा, संघीय संतुलन। तर्क दिया जा रहा है कि 131वां संशोधन असल में महिलाओं के लिए आरक्षण का विधेयक था ही नहीं, बल्कि यह तो एक परिसीमन विधेयक था, जिसे महिलाओं के अधिकारों की आड़ में चुपके-से घुसा दिया गया था। इसमें एक समस्या है। 106वां संशोधन, जिसे 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उसके कार्यान्वयन को जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर बना दिया गया था। विपक्ष ने उस प्रावधान के पक्ष में मतदान किया था। खड़गे ने सदन में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी; फिर भी 'हां' में वोट दिया, क्योंकि 'नहीं' में वोट देना राजनीतिक दृष्टि से नुकसानदायक हो सकता था। बीते 17 अप्रैल को उनका दिखावा और कार्यान्वयन अलग-अलग हो गए। 2023 में विपक्ष ने जिस परिसीमन को स्वीकार किया था, उसे सक्रिय करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता थी। 131वां संशोधन ही वह तंत्र था। जब यह सामने आया, तो विपक्ष ने इसे उन्हीं कारणों से आपत्तिजनक पाया, जिन्हें उसने 2023 के अधिनियम के पक्ष में मतदान करके स्वीकार कर लिया था। विपक्ष ने स्वयं को उस 'साधन' के प्रति तो प्रतिबद्ध कर लिया, लेकिन उसे संचालित करने वाले हर 'तंत्र' पर आपत्ति जताई। इस तरह नौ विधेयक पेश किए गए, नौ बार आपत्तियां जताई गईं। एक बार संविधान संशोधन पारित हुआ, लेकिन महिला आरक्षण लागू न हो सका।

मौजूदा रुझानों के हिसाब से, 19वीं लोकसभा में 543 सदस्यों में से 75 से 80 महिलाएं होंगी। भारत 143वें स्थान पर ही बना रहेगा। टैक्स कोड, रक्षा बजट और शिक्षा नीति बनाने वाली समिति में पुरुषों का ही दबदबा बना रहेगा। आबादी का 48 प्रतिशत। लोकसभा का 13.6 प्रतिशत। 143वां स्थान। तीस साल में कोई बदलाव नहीं।

विपक्ष ने, 1996 से लेकर अब तक अपने हर भाषण में महिलाओं के लिए आरक्षण का जोरदार और बार-बार समर्थन किया है। और इसके लिए उन्हें कोई चुनावी कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। दूसरी ओर, आपत्तियां भी जोरदार और बार-बार उठाई गई हैं, पर उनकी कीमत पूरी तरह से पिछले तीन दशकों से महिलाओं को ही चुकानी पड़ी है। दिखावा और गणित, दोनों अलग-अलग कहानियां कहते हैं। उनमें से केवल एक ही सच है।

बांग्लादेश से रिश्तों में हसीना फैक्टर की बाधा

शशिधर खान

बांग्लादेश की नई सरकार के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान दिल्ली से विदा होते-होते शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की भारत सरकार से गुजारिश करके द्विपक्षीय रिश्ते में तल्खी छोड़ गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के खिलाफ भड़के व्यापक जनता-छात्र विद्रोह को कुचलने में विफल होने के बाद शेख हसीना को जुलाई-अगस्त, 2024 में सत्ता के साथ-साथ देश भी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने भागकर भारत में पनाह ली और यहीं निर्वासन में रह रही हैं। शेख हसीना ने अपनी प्रबल प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा के खिलाफ सारे कानूनी हथकंडे अपनाए थे ताकि वो कभी-भी उनके लिए चुनौती न बन सकें। खालिदा जिया की पार्टी को प्रतिबंधित करना और उनके खिलाफ मुकदमे चलाकर जेल में डालना उसका हिस्सा था। शेख हसीना के लगातार सत्ता में बने रहने के पीछे भारत के कथित अप्रत्यक्ष सहयोग की भी बात आसपड़ोस और अंतरराष्ट्रीय हलकों में होती थी। लेकिन भारत के हित में सबसे अच्छी बात यह रही कि शेख हसीना ने चीन, पाकिस्तान से दूरी और भारत से नजदीकी बनाए रखी। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों को शेख हसीना ने सिर उठाने नहीं दिया और भारत की पूर्वोत्तर सीमा में उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाई। भारत से नजदीकी जरूर बढ़ी, मगर अपने देश में विरोधियों की आवाज दबाने के कारण शेख हसीना की लोकप्रियता कम होती गई। यहां तक कि जुलाई, 2024 में भड़के विद्रोह का तेवर समझने के बजाय अवामी लीग सरकार ने उसे कुचलने में कोई

कसर नहीं छोड़ी। उसके जवाब में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्ववाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग समर्थकों को निशाना बनाया। फरवरी, 2026 के आम चुनाव में बांग्लादेश की जनता ने बीएनपी के प्रति भरोसा जताया और उसके नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। नई सरकार ने सभी को साथ लेकर चलने के साथ-साथ भारत से संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। बीएनपी सरकार के किसी राजनयिक की यह पहली विदेश यात्रा थी, जब उसके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान गत हफ्ते भारत आए। इस नई सरकार को अंतरिम सरकार की तरह चीन, पाक से नजदीकी रखनी है या नहीं, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, मगर भारत से अच्छे रिश्ते बनाने पर खलीलुर रहमान ने जोर दिया है। लेकिन साथ-साथ शेख हसीना को ढाका को सौंपने पर भी जोर दिया है। भारत-बांग्लादेश रिश्ते में आज भी हसीना महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहली बार ऐसा हुआ, जब तारिक रहमान के नेतृत्ववाली नई सरकार के किसी मंत्री ने भारत आकर आधिकारिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका को सौंपे जाने का मामला उठाया।

ईरान के अंदर क्या चल रहा है: बाहर जंग, अंदर खींचतान

जाहिद खान

ईरान इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। बाहर से दबाव है। जंग का माहौल है। समंदर के रास्तों पर तनाव है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है। इस्राइल अपना दबाव बनाए हुए है। ऐसे वक्त में किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ मिसाइल या फौज नहीं होती, बल्कि ये होती है कि उसके अंदर फैसले किस तरह लिए जा रहे हैं। अगर ऊपर से एक बात कही जाए और अगले ही दिन उसी बात का रुख बदलता दिखे तो सवाल उठना लाजिमी है।

असल मसला यहीं से शुरू होता है। एक तरफ ऐसा संदेश गया कि होर्मुज का रास्ता आसान किया जा रहा है, दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद उसी मोर्चे पर सख्ती बढ़ती दिखी। अब आम इंसान चाहे किसी भी देश का हो, वो यही पूछेगा कि आखिर सच क्या है। क्या फैसला पहले सोच-समझकर लिया गया था या कोई बयान जल्दबाजी में दे दिया गया क्योंकि होर्मुज कोई मामूली जगह नहीं है। वह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, पूरी दुनिया की सांस की नली जैसा रास्ता है। वहां एक लाइन ऊपर नीचे होने से तेल, कारोबार, जहाज, दबाव, सब कुछ बदल जाता है।

यहीं से ईरान के अंदर की तस्वीर पर नजर जाती है। वहां सिर्फ एक दफ्तर से देश नहीं चलता। अलग-अलग ताकतें हैं, अलग-अलग जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं। कोई मैदान देखता है, कोई कूटनीति देखता है, कोई सुरक्षा का बड़ा दायरा देखता है। जब सब एक दिशा में हों तो देश लोहे की तरह खड़ा रहता है लेकिन जब लहजे अलग दिखने लगें तो बाहर वाला दुश्मन तुरंत समझ जाता है कि यहां दरार खोजी जा सकती है।

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये नहीं कि किसने क्या कहा। असली बात ये है कि किसकी बात जमीन पर चली। अगर कोई बड़ा बयान आता है और उसके बाद एक्शन बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि या तो अंदर सलाह एक नहीं थी या फिर आखिरी फैसला

कहीं और से होना था। यही वह जगह है जहां से बाहर की दुनिया अपने मतलब की कहानियां बनाती है। अमेरिका जैसे देश ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। जहां थोड़ा सा खालीपन दिखा, वहीं अपनी बात ठूंस दी, अपना नैरेटिव खड़ा कर दिया और दुनिया को ये जताने लगे कि सामने वाला बिखर रहा है।

यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। जंग के दिनों में फैसले सिर्फ किताब देखकर नहीं लिए जाते। उस वक्त हर बात में मैदान, सुरक्षा, सियासत, इज्जत और आने वाले दिनों की चाल सब शामिल होती है इसलिए कभी-कभी ऊपर से जो दिखता है, अंदर की कहानी उससे अलग होती है। हो सकता है कोई बयान दबाव कम करने के लिए आया हो। हो सकता है कोई लाइन बाहर को संदेश देने के लिए छोड़ी गई हो और ये भी हो सकता है कि अंदर सचमुच मतभेद हों, लेकिन जब एक के बाद एक संकेत उलझे हुए आने लगें, तब शक मजबूत होने लगता है कि मामला सिर्फ रणनीति का नहीं, अंदरूनी असहमति का भी है।

ईरान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ये मानी गई कि वह दबाव में भी जल्दी टूटता नहीं। वहां फैसले भले देर से हों, लेकिन एक बार लाइन तय हो जाए तो फिर उस पर डटे रहने की आदत है। अगर अब वही देश ऐसा दिखने लगे कि अलग-अलग ताकतें अलग सुर में बोल रही हैं तो ये उसके लिए अच्छा इशारा नहीं क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, जंग दिमाग, मनोबल और संदेश में भी जीती जाती है। दुश्मन ये देखता है कि सामने वाला कितना थका, कितना टूटा, कितना बंटा और अगर उसे अंदर की खींचतान की बू आ जाए तो वह और दबाव बढ़ाता है।

इसका दूसरा पहलू भी है। कई बार बाहर वालों को जो बिखराव दिखता है, वह असल में किसी बड़े सिस्टम की अंदरूनी बहस भी होती है। फर्क बस इतना है कि ऐसी बहस अगर बाहर लीक हो जाए तो उसका नुकसान बहुत होता है क्योंकि फिर लोग फैसला नहीं, फूट देखने लगते हैं। आज ईरान के साथ यही हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि वहां असली लाइन कौन तय कर रहा है। कौन सख्त है, कौन नरम है, कौन बातचीत चाहता है, कौन मोर्चा कड़ा रखना चाहता है और जब ये सवाल आम हो जाएं तो समझिए कि दुश्मन अपना काम आधा कर चुका है।

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि जंग के बीच एक देश को अपने लोगों में यकीन पैदा करना होता है। लोगों को लगना चाहिए कि ऊपर बैठे लोग एक हैं, समझदार हैं और हर कदम सोचकर उठा रहे हैं। अगर आम लोग ही उलझन में पड़ जाएं कि अभी सच क्या है तो यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। बाहर की नाकेबंदी, भीतर का दबाव, चारों तरफ दुष्प्रचार और ऊपर से अलग-अलग आवाजें, ये मिलकर किसी भी देश को मुश्किल में डाल सकती हैं।

आखिर में बात सीधी है। ईरान इस समय सिर्फ बाहर की जंग नहीं लड़ रहा, उसे अपने भीतर की तस्वीर भी संभालनी है। अगर अंदर की लाइन साफ रही तो बाहर का दबाव भी झेला जा सकता है लेकिन अगर अंदर ही बात उलझी रही तो दुश्मन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंग के दिनों में बंदूक से पहले भरोसा बचाना पड़ता है और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वही होता है, जब बाहर का हमला कम और अंदर की उलझन ज्यादा दिखने लगे।

विकास और सुशासन के मुद्दों पर भी काम करे मीडिया

प्रो. संजय द्विवेदी

मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएं न हों यह संभव नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएं मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिए जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है। विकास पत्रकारिता को पाठ्यक्रम के साथ मीडिया कर्म का भी हिस्सा होना चाहिए।

भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी' , इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी और झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहां विस्तृत और परिवर्तित हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएं अलग हो गयी। बाद के दिनों में सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गए हैं। यहां तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं।

एक समय में विकसित और विकासशील देशों की

बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजू हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकी माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहां यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन(संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है।

विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुंची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराईयां हमारी पंचायतों तक नहीं पहुंच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुंच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे-धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख-दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके।

हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएं बढ़ गई हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गए हैं, किंतु इनसे आम-आदमी गायब है। चैनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है। जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच सकते, मीडिया उन तक पहुंचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएं।

हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चिंताएं अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिंताएं कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएं हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयं रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब मांगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी।

आखिर कब तक होगा अमेरिका और ईरान में सीजफायर?

संजय गोस्वामी

आज कल न्यूज़ में ईरान - अमेरिका इजराइल के युद्ध का बार बार दिखाना बोर कर रहा है अभी देखा तो कभी ऐ देखने को मिलता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कभी दोनों में सीजफयार होगा और ट्रम्प और ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान में शान्ति वार्ता करेंगे, जबकी अमेरिका ने ईरान को आर्थिक नुकसान हेतु स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर नेवल ब्लॉकेड लागू कर दिया है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है।फिर तुरंत ही ऐ समाचार मिलता है कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और हॉर्मुज जल-डमरू-मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया।मोदीजी ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने सभी क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यंक्तक एक और शान्ति वार्ता पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में शान्ति वार्ता होंगी उधर इजराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर अटैक कर रहा है जो एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल है, जिसका एक सक्रिय अर्धसैनिक विंग भी है; लेबनान सरकार ने मार्च 2026 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।लेकिन हिज़्बुल्लाह पहले लेबनान में चुनाव में भाग भी लिया और वहाँ के प्रधानमंत्री को भी मारा है जो लोग इस संघठन के बारे में नहीं जानते उसके इतिहास पर नजर डाले तो वो लेबनान में अमेरिका के एक बस को बम से उड़ाया और मरकावा नरसंहार 2006 के बाद 2026, में 100 इजरायली टैंक मारने का हिज़्बुल्लाह ने किया दावा ज़ सैन्य विश्लेषक दोनों पक्षों के शस्त्रागारों के बीच भारी आर्थिक असमानता की ओर भी इशारा करते हैं और वो इजराइल से बात नहीं करेगा उसने

कई आतंकी गतिविधियों को खाड़ी देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है यहाँ तक की 2017 में आईएसआईएस के साथ मुठभेड़ भी हुई हिज़्बुल्लाह ने पूर्वी अलेप्पो आक्रमण (जनवरी-अप्रैल 2017) और फरवरी 2017 में के विरुद्ध अल-बाब की लड़ाई में भाग लिया। हिज़्बुल्लाह ने आईएसआईएस दारा आक्रमण (फरवरी-जून 2017) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उसे कई हताहतों का सामना करना पड़ा सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान, हिज़्बुल्लाह के दुष्प्रचार ने सीरियाई विपक्ष को पूरी तरह से तकफ़ीरी बताकर, असद शासन के विरोधियों को अमानवीय दिखाने का प्रयास किया है मुख्य रूप से इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड सीरिया को दर्शाता है, जो एक उग्रवादी जिहादी समूह है और जिसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है।अत: इजराइल और बेरूत में चल रहें युद्ध अब सीजफ़ायर की ओर जा रहा है जिसे अमेरिका ने लेबनान के प्रधानमंत्री व इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच शान्ति वार्ता की पेशकश की है आतंकवाद आज सभी देशों के लिए खतरा है जिससे वहाँ निर्दोष लोगों की हत्या होती है आखिर कब तक चलेगा अमेरिका और ईरान में सीजफायर जो लेबनान युद्ध के कारण सफ़ल नहीं हो पा रहा है और इस युद्ध से हर चीज के दाम 20ल से अधिक तक बढ़ गए हैं जो बेबजह जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है अब लगता है ऐ युद्ध ना अमेरिका चाह रहा है और ना ही ईरान इसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्री के बीच 40 मिनट की वार्ता हुई।

खाने के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है हानिकारक असर!

पैदल चलना शरीर के लिए लाभदायक है। इससे वजन घटाने और मधुमेह रोगियों को लाभ होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खाने के बाद टहलना एक चुनौती हो सकती है। जी हां, डॉ. अनुज के अनुसार, खाने के बाद तीन छोटी सैर (प्रत्येक 10 मिनट) रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में 30 मिनट की एक लंबी सैर से अधिक प्रभावी हो सकती है। यह बेहतर परिणाम देता है, खासकर अगर इसे खाने के तुरंत बाद किया जाए।

डायबेटोलोजिया पत्रिका में प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, भोजन के बाद 10 मिनट की सैर से टाइप-2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार होता है। भोजन के बाद टहलने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और पाचन के दौरान ग्लूकोज का उपयोग बेहतर होता है, जिससे शर्करा के स्तर में तेजी से होने वाली वृद्धि कम होती है।

खाने के बाद टहलने के फायदे

1. ब्लड शुगर नियंत्रित करें – खाने के बाद शरीर को अधिक इंसुलिन की जरूरत होती है। पैदल चलने से शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है, जिससे रक्त शर्करा का शीघ्र उपयोग होता है और स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

2. हृदय स्वास्थ्य- नियमित रूप से हल्का व्यायाम जैसे टहलना हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है।

3. वजन प्रबंधन- मधुमेह रोगियों के लिए वजन कम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

झारखंड के जन स्वास्थ्य अभियान में कार्यरत डॉक्टर अनुज कुमार कहते हैं कि खाने के बाद टहलना एक अच्छा व्यायाम है, लेकिन कुछ लोगों को खाने के बाद टहलने से बचना चाहिए। विशेषकर किसी भी पेट की सर्जरी के बाद।

खाने के बाद किसे टहलना नहीं चाहिए?

गैस्ट्रोपेरेसिस से पीड़ित लोगों में – इससे मतली या सूजन हो सकती है।

गंभीर हृदय रोग से पीड़ित लोगों में – खाने के बाद, रक्त प्रवाह पाचन पर केंद्रित होता है और परिश्रम के कारण हृदय पर दबाव पड़ सकता है।

हाइपोग्लाइसीमिया के रोगी – इंसुलिन या कुछ दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों को चलते समय निम्न रक्त शर्करा का अनुभव हो सकता है।

आईबीएस) से पीड़ित लोग – यह एक गंभीर पाचन समस्या है। खाने के बाद टहलने से इसके लक्षण बढ़ सकते हैं।

कुछ लोगों को खाने के बाद चलने से चक्कर आना, सीने में दर्द या अत्यधिक थकान महसूस होती है, इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए।

गर्मी में आग की भट्टी बन जाती है किचन, अपनी रसोई को ठंडा रखने के लिए करें ये 5 काम

कभी-कभी गर्मियों में कूलर या एसी के बिना रहना असंभव लगता है। यह मौसम उन लोगों के लिए विशेष रूप से थकाने वाला होता है जो दिन-रात रसोई में खाना पकाने में बिताते हैं। अधिकतर महिलाओं को लंबे समय तक रसोई में काम करना पड़ता है। उबलते बर्तनों, गर्म ओवन और खराब वेंटिलेशन के कारण रसोईघर अक्सर भट्टी में बदल जाता है, जिससे खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह आप कुछ आसान टिप्स अपनाकर किचन को ठंडा और आरामदायक बना सकते हैं, जिससे किचन में गर्मी काफी हद तक कम हो सकती है और आप आराम से खाना बना सकते हैं।

पर्दे और हरियाली का उपयोग करें

यदि आपके रसोईघर में बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन्हें दिन के समय बंद रखें, प्रकाश और गर्मी को रोकने के लिए हल्के रंग के सूती पर्दे का उपयोग करें। आप अलमारियों पर इनडोर कूलिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। हरियाली आसपास के वातावरण को अधिक ठंडा और आरामदायक बना सकती है। इसके अलावा आप रसोईघर के बाहर भी कुछ पौधे लगा सकते हैं। रसोईघर से गर्मी बाहर निकालने के लिए समय-समय पर खिड़की भी खोलें।

चिमनी और एग्जॉस्ट पंखों का उपयोग करें

यदि आपके रसोईघर में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन है तो गर्मियों में उनका प्रयोग करें। वे धुआं, भाप और नमी को कम करने में मदद करते हैं तथा शरीर को अधिक आरामदायक और सूखा रखते हैं। इससे आपका रसोईघर लंबे समय तक ठंडा रहेगा।

सुबह खाना पकाएँ

गर्मियों के मौसम में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गर्मी बहुत अधिक होती है। इसलिए, गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी खाना पकाने की कोशिश करें। कई लोग दोपहर का भोजन सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच बनाना शुरू कर देते हैं, जब सूरज चमक रहा होता है। नाश्ता तैयार करने के बाद, अपना दोपहर का भोजन जल्दी से पकाने की कोशिश करें, खासकर उन चीजों को जिन्हें तैयार करने में लंबा समय लगता है।

अगर घर में नहीं आ रही है पॉजिटिव वाइब्स? तो आज ही ट्राई करें सही कलर, फर्नीचर और डेकोरेशन टिप्स

हर व्यक्ति एक ऐसा घर खरीदने का सपना देखता है जहां उसे शांति, सुखद और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो। इसलिए लोग घर की साज-सज्जा और वास्तु पर तो विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन जब बात सजावट और फर्नीचर की आती है तो लोग सस्ते सामानों की ओर भागते हैं। वहीं, अगर आप अपने घर को थोड़ी समझदारी और रचनात्मकता के साथ सजाते हैं, तो घर न सिर्फ खूबसूरत दिखता है, बल्कि उसमें रहने वाले लोग भी खुश रहते हैं। आज इस लेख में हम सराफ फर्नीचर के सीईओ रघुनंदन सराफ से जानेंगे कि कैसे आप कुछ खास टिप्स और आइडियाज से अपने लिविंग रूम को ज्यादा सकारात्मक, आकर्षक और आरामदायक बना सकते हैं।

सही रंगों का उपयोग

पूरा दिन बाहर बिताने के बाद घर आने पर हर कोई शांति और आराम पाना चाहता है। इसलिए, आपको अपने कमरे की दीवारों पर बेज, हल्का भूरा और टेराकोटा जैसे रंगों पर विचार करना चाहिए। ये रंग आंखों को सुखा देते हैं। इसके अलावा, आपको अपने घर में लकड़ी का फर्नीचर भी रखना चाहिए, जिसमें डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल और बुकशेल्फ़ शामिल हैं। ऐसा करने से आप अपने घर में प्रवेश करते ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे।

लाल और सुनहरे रंग में सजावट

रघुनंदन सराफ कहते हैं कि अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और चमक लाना चाहते हैं तो आपको लाल और सुनहरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल रंग जोश और जुनून का प्रतीक है तथा सुनहरा रंग धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। आपको घर के लिविंग रूम में लाल कुशन, सुनहरे बॉर्डर वाले दर्पण, लाल कुर्सियां ??और सुनहरे डिजाइन वाले लैंप और फूलदान रखने चाहिए।

हरे पौधे लगाएँ

घर को ताजा रखने के लिए आपको इनडोर पौधे लगाने चाहिए। मनी प्लांट और बांस जैसे पौधे सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। ये न केवल दिखने में सुंदर हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं।

बहुउपयोगी फर्नीचर

सराफ का कहना है कि यदि आपका घर छोटा है और आपके पास फर्नीचर के लिए कम जगह है, तो आप सोफा-कम-बेड, स्टोरेज के साथ बेंच, एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल और मल्टीफंक्शनल ओटोमन जैसे फर्नीचर खरीद सकते हैं और जगह भी बचा सकते हैं।

कांच या दर्पण वाला फर्नीचर

यदि आप अपने घर को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप कांच या कांच का फर्नीचर खरीद सकते हैं। आप कांच के टॉप वाली साइड टेबल या दर्पण वाली डाइनिंग टेबल खरीदकर जगह को बड़ा दिखा सकते हैं। हालाँकि, वास्तु के अनुसार आपको पूर्व या उत्तर दिशा में दर्पण या खिड़की लगानी चाहिए।

फेंग शुई से संबंधित आसान फर्नीचर सेटिंग टिप्स

अगर आप घर का माहौल शांत और खुशहाल रखना चाहते हैं तो आपको कुछ फेंगशुई टिप्स अपनाने चाहिए। आपको लिविंग रूम का सोफा दरवाजे की ओर रखना चाहिए, ताकि आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। घर के फर्नीचर के कोने नुकीले नहीं होने चाहिए और घर में सामान ज्यादा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। घर में सोफा और कुर्सियां हमेशा गोलाकार में रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

कपड़े धोने के बाद नहीं होगा प्रेस करने का झंझट, बस अपनाएं ये स्मार्ट हैक्स

कपड़े प्रेस करना हम सभी के लिए निश्चित रूप से उबाऊ होता है। विशेषकर, कोई भी व्यक्ति गर्मी की दोपहर में गर्म लोहे के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। ऊपर से गर्मी, उमस और दिनभर भागदौड़ के कारण हम अपने कपड़ों को प्रेस करने में अपना समय और मेहनत दोनों बर्बाद करते हैं। हो सकता है कि आप भी गर्मियों में कपड़ों को प्रेस नहीं करना चाहते हों, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां, कुछ सरल उपाय हैं जिनका पालन करके आप अपने कपड़ों को बिना प्रेस किए भी ताजा और सिलवट रहित रख सकते हैं।

कपड़ों को बिना प्रेस किए भी सिलवटों से मुक्त रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सही कपड़े के चयन से लेकर कपड़े धोने के कुछ टिप्स तक, कई सरल टिप्स हैं जो आपका समय, प्रयास और पसीना बचा सकते हैं। इसलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ सरल हैक्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना इस्त्री किए भी कपड़ों को रिंकल फ्री रख सकते हैं-

कपड़ों का चयन बुद्धिमानी से करें

जब आप गर्मियों के मौसम में कपड़े खरीद रहे हों तो आपको केवल उसके हल्के वजन पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। यकीनन, इस मौसम के लिए कपास एक अच्छा कपड़ा माना जाता है, लेकिन इसे काफी प्रेस करना पड़ता है। इसलिए, आपको ऐसे कपड़े का चयन करना चाहिए जिसे इस्त्री करने की आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए, आप लिनेन मिश्रण से लेकर रेयान, निट और स्ट्रेच फैब्रिक तक का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको कपड़े के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कपड़े खरीदते समय टैग पर रिंकल फ्री या नो आयरन की जांच कर लें।

कपड़ों को समझदारी से धोएं

आप अपने कपड़े कैसे धोते हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, मशीन में एक साथ बहुत सारे कपड़े न डालें जिससे उन्हें इधर-उधर घूमने के लिए जगह न मिले। इसके अलावा, कपड़े धोने के चक्र में फैब्रिक सॉफ़्नर या आधा कप सफेद सिरका मिलाएं, जिससे झुर्रियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा, धोने के बाद हर कपड़े को अच्छी तरह हिलाएं और फैलाएं। शर्ट को हैंगर पर लटकाएं और उन्हें सही आकार में सुखाएं। इसके अलावा, झुर्रीदार कपड़ों के साथ ड्रायर में 2-3 बर्फ के टुकड़े डालें और 10 मिनट तक चलाएं। भाप से सिलवटें अपने आप हट जाएंगी।

घर पर बनाएं झुर्रियों से राहत देने वाला स्प्रे

आप कपड़ों पर प्रेस किए बिना ही झुर्रियां हटाने के लिए घर पर ही रिंकल रिलीफ स्प्रे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक कप डिस्टिल्ड वाटर, एक चम्मच फैब्रिक सॉफ्टनर और एक चम्मच रबिंग अल्कोहल मिलाएं। आवश्यकतानुसार कपड़ों पर हल्का स्प्रे करें, फिर हाथ से सीधा करें। इसे 10 मिनट तक लटका कर सुखाएं।

स्टीमर के बिना भाप बनाने की तरकीब

यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो भी आप कपड़ों को सिलवट रहित बना सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी से नहाते समय कपड़ों को बाथरूम में लटका दें। दरवाजा बंद कर दें और भाप को 10-15 मिनट तक अपना काम करने दें। इसके बाद अपने हाथों की मदद से कपड़ों को सीधा करें। सिलवटें आसानी से हटा दी जाएंगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार मुंबई के अस्पताल में भर्ती

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 85 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री को दो दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शरद पवार की सेहत को लेकर सूत्रों के हवाले से बताया कि उन्हें नियमित जांच के सिलसिले में अस्पताल लाया गया। उनकी हालत गंभीर नहीं है। गौरतलब है कि वयोवृद्ध राजनेता शरद पवार हाल ही में व्हीलचेयर पर बैठकर संसद पहुंचे थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पहुंचे पवार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए थे। इससे पहले पवार को इसी वर्ष फरवरी में पुणे के एक अस्पताल में दो बार भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक फरवरी में उन्हें छाती में संक्रमण और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद डॉक्टरों से दिखाया गया था।

अपनी महिला विरोधी छवि नहीं मिटा सके सपा-कांग्रेस : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महिला आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के विरोध के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस विकल्प का दुरुपयोग किया है, जिसके तहत वे अपनी महिला विरोधी छवि को मिटाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ ने ये टिप्पणियां संविधान संशोधन विधेयक की हार के विरोध में निकाली गई जन आक्रोश महिला पदयात्रा में भाग लेने के बाद कीं। पदयात्रा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, उनके कर्म महिला विरोधी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस विकल्प का दुरुपयोग करने की कोशिश की है, जिसके तहत वे अपनी महिला विरोधी छवि को मिटाना चाहते थे।

डीएमके के खिलाफ भ्रम की साजिश हुई फेल : कनिमोझी

चेन्नई। डीएमके सांसद कनिमोझी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने इन प्रयासों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है और जीत की ओर अग्रसर है। मतदान से पहले बोलते हुए कनिमोझी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) जैसे उपायों और छापेमारी जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयों का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने और गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। कनिमोझी ने कहा कि एसआईआर समेत कई मोर्चों पर भ्रम पैदा करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन डीएमके ने सक्रियता से काम किया है और इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। पार्टी की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को दूसरा कार्यकाल मिलना तय है।

चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस-डीएमके को बताया महिला विरोधी

चेन्नई। एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रस्तावित परिसीमन का बचाव करते हुए इसे अपरिहार्य बताया और कहा कि इस योजना के तहत किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की इसके विरोध के लिए आलोचना भी की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नायडू ने राहुल गांधी और एम के स्टालिन के इस दावे पर सवाल उठाया कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को सफलतापूर्वक रोक दिया है। नायडू ने कहा कि दोनों पार्टियों को यह स्पष्ट करना होगा कि यह किस तरह की जीत है, और आरोप लगाया कि इस कदम का विरोध करके उन्होंने राजनीतिक आरक्षण की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उनकी यह टिप्पणी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद आई है, जिससे प्रस्तावित सुधार रुक गए हैं।

कांग्रेस में प्रियंका को लाओ राहुल से नहीं चलेगा: तेज प्रताप

पटना। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व के लिए प्रियंका गांधी की वकालत करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता पर अविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केवल प्रियंका गांधी ही इसे चला सकती हैं; वह इंदिरा गांधी जैसी हैं। राहुल गांधी से चलने वाला नहीं है, यात्रा पर जाकर, बुलेट पर बैठकर। नीतीश कुमार जी चले गए, कोई और मुख्यमंत्री बन गया, उनका मकसद क्या है? तेज प्रताप यादव की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार के राज्य की राजनीति से हाल ही में बाहर निकलने के बाद उन्हें समझौते में फंसा हुआ बताया था। भाजपा के सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जगह बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं।

अजित डोभाल की सऊदी अरब यात्रा के बीच पाक को लगा बड़ा झटका!

सूडान-पाकिस्तान का रक्षा समझौता टला

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया और अफ्रीका में तेजी से बदलते हालात के बीच भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब की रणनीतिक गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का सऊदी अरब दौरा और पाकिस्तान द्वारा सूडान को हथियार आपूर्ति के बड़े समझौते को रोकना, दोनों घटनाएं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान देने से जुड़े लगभग डेढ़ अरब डॉलर के समझौते को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब सऊदी अरब ने इस समझौते के वित्त पोषण से हाथ खींच लिया और पाकिस्तान को इसे समाप्त करने का संकेत दिया। बताया जाता है कि यह सौदा अपने अंतिम चरण में था और इसकी मध्यस्थता भी सऊदी अरब ने ही की थी, लेकिन बाद में उसने अपनी रणनीति बदल दी।

पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह अपने रक्षा निर्यात को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। हम आपको बता दें कि सूडान में पिछले तीन वर्षों से सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष जारी है, जिसने गंभीर मानवीय संकट को जन्म दिया है। यह संघर्ष अब केवल आंतरिक नहीं रहा, बल्कि इसमें बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा भी शामिल हो गई है। लाल सागर के किनारे स्थित और सोने के बड़े उत्पादक देश के रूप में सूडान का सामरिक महत्व काफी अधिक है।

इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वहां दोनों देश अलग अलग पक्षों के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। जहां सऊदी अरब सूडान की सेना के करीब है, वहीं अमीरात पर रैपिड सपोर्ट फोर्स को रसद सहायता देने के आरोप लगे हैं, हालांकि वह इन्हें खारिज करता रहा है। ऐसे में सऊदी अरब का इस सौदे से पीछे हटना यह संकेत देता है कि वह अफ्रीका में प्रत्यक्ष या परोक्ष संघर्षों से दूरी बनाना चाहता है।

रिपोर्टों के अनुसार कुछ पश्चिमी देशों ने भी सऊदी अरब को अफ्रीका में प्रॉक्सी संघर्षों से दूर रहने की सलाह दी थी। इसके बाद मार्च महीने में रियाद में सूडानी सेना और सऊदी अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद इस समझौते के वित्त पोषण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

देखा जाये तो इस घटनाक्रम का असर केवल सूडान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान और लीबिया के बीच प्रस्तावित लगभग चार अरब डॉलर का एक और रक्षा समझौता भी अब खतरे में बताया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि सऊदी अरब अपनी क्षेत्रीय रणनीति की व्यापक समीक्षा कर रहा है और उन गतिविधियों से दूरी बना सकता है जो उसे जटिल संघर्षों में उलझा सकती हैं। दूसरी ओर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का सऊदी अरब दौरा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति खाड़ी देशों से आती है, इसलिए किसी भी व्यवधान का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

सांसदों के अपमान पर सियासी घमासान

पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करते हुए निचले सदन के सदस्यों पर आरोप लगाकर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। बिरला को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि मैं लोकसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 222 के प्रावधानों के तहत भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न का नोटिस देता हूं, क्योंकि उन्होंने 18 अप्रैल, 2026 को प्रसारित अपने संबोधन/भाषण में लोकसभा सदस्यों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 की हार के बाद यह संबोधन दिया गया, क्योंकि विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने 29 मिनट के भाषण में विपक्षी दलों द्वारा विधेयक को रोकने की आलोचना की और विपक्ष के सदस्यों के मतदान पैटर्न पर सीधा प्रहार करते हुए उन पर इरादे थोपे।

वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे निर्वाचित प्रतिनिधि पर सवाल उठाना न केवल व्यक्तिगत हमला है, बल्कि संसद के अधिकार और भारत की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि संसद की गरिमा और उसके सदस्यों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाएँ, ताकि ऐसे उल्लंघन न तो अनदेखे किए जाएँ और न ही दोहराए जाएँ।

वेणुगोपाल के पत्र को टैग करते हुए, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री के तथाकथित राष्ट्र संबोधन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोकसभा में उनके नापाक मंसूबों की हार के बाद आया है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी - विपक्ष की पूर्ण एकता और एकजुटता।

परिसीमन जोड़ महिला आरक्षण टाल रही केंद्र सरकार : जयराम रमेश

सोनिया-राहुल के पत्र का जिक्रकर कहा- फिर देरी क्यों?

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने में देरी करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग कर चुके थे, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर सोती रही और बाद में इसे परिसीमन से जोड़कर टालने की कोशिश की।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा से पारित कराने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में बहुमत का उपयोग कर सरकार इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराए।

सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इस कानून के समर्थन में रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की पहल सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस ने की थी, जो बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुई।

वहीं रमेश ने राहुल गांधी का वह पुराना पत्र भी साझा किया, जिसमें उन्होंने संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा था। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा था कि महिला आरक्षण बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हो चुका था, लेकिन उसके बाद लोकसभा में विभिन्न कारणों से अटका रहा।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि अगर सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गंभीर है, तो महिला आरक्षण बिल को बिना शर्त समर्थन देकर संसद के आगामी सत्र में पारित कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि और देरी होने पर अगले आम चुनाव से पहले इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा।

विपक्षी दल ने मांग की कि केंद्र सरकार मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू करे और इसके लिए संसद के मानसून सत्र या मई अंत तक नया विधेयक लाए।

यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार का संविधान (131वां संशोधन) विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया। इस बिल में महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव था।

महिला आरक्षण विधेयक क्यों नहीं हुआ पास?

मतदान में 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 230 सांसदों ने विरोध में वोट दिया। कुल 528 मतों में से बिल पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट जरूरी थे, जो सरकार को नहीं मिल सके।

प्रस्तावित विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की योजना थी। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सीटें बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था।

खेल
प्रमुख समाचार

आज दमदार राजस्थान का मुकाबला संघर्षरत लखनऊ से

लखनऊ। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के इस जरूरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बुधवार को काफी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी और यह सही भी है। उनका क्रिकेट फीयरलेस यंग बैटिंग और एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक से चला है जिसने अक्सर अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी ओर, लखनऊ अपने होम ग्राउंड पर काफी प्रेशर में लौटा, लगातार निराशाजनक नतीजों के बाद रिदम और कंसिस्टेंसी की तलाश में।

यह मुकाबला कई मायनों में, स्टाइल में एक क्लासिक कंट्रास्ट है। एक तरफ राजस्थान का फीयरलेस यूथ-ड्रिवन अप्रोच है, और दूसरी तरफ लखनऊ, जो अपने सीजन को होम ग्राउंड पर और गहरे संकट में जाने से रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है। लखनऊ ने अब तक 6 मैचों में से सिर्फ 2 जीते हैं, और वे अभी तीन मैचों में हार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हालांकि कुछ इंडिविजुअल पल क्वालिटी के रहे हैं, लेकिन वे एक यूनिट के तौर पर पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता रही है।

वहीं राजस्थान ने 6 मैचों में से 4 जीते हैं। भले ही उन्हें हाल ही में कुछ झटके लगे हों, लेकिन इस मैच में उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर, बैलेंस और फॉर्म अभी भी अपने अपोनेंट्स से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। लखनऊ के लिए बैटिंग यूनिट सबसे बड़ी चिंता का विषय रही है। मिचेल मार्श और एडेन मार्करम ने अच्छी शुरुआत दी है, लेकिन उस शुरुआत को बड़े, मैच जिताने वाले योगदान में नहीं बदला है। निकोलस पूरन एक मुश्किल सीजन से गुजर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में टाइमिंग और कंसिस्टेंसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कप्तान, ऋषभ पंत ने कुछ असरदार कैमियो के साथ इरादा दिखाया है, लेकिन एक कमांडिंग पारी जो सच में टीम को संभाले, इस सीजन में अभी तक नहीं आई है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 750 अंक चढ़ा निफ्टी 24576 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में बढ़त के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार (21 अप्रैल) को मजबूती के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर आगे बढ़ने की उम्मीद से बाजार में पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक समेत अन्य बैंकिंग शेयरों और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी से भी बाजार को सपोर्ट मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 78,617.16 अंक पर खुला। जबकि सोमवार को यह 78,520.30 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 79,367 अंक के हाई तक गया। अंत में 753.03 अंक या 0.96 फीसदी की बढ़त लेकर 79,273.33 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 24,374 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 24,600 के पार तक गया। अंत में 211.75 अंक या 0.87 फीसदी की बढ़त के साथ 24,576 . 60 पर बंद हुआ।

एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान

नईदिल्ली। भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान संकट के बीच ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और बुकिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी है। आम लोगों को किसी तरह की कमी या अचानक महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया गया है। साथ ही, गैस सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके। सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को सख्ती से लागू किया है।

ईरान युद्ध के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार बरकरार

नईदिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए ऊर्जा संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है, जिससे भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल भारत की ग्रोथ 7.4% थी, जो इस साल थोड़ी कम होकर 6.4% रहेगी, लेकिन अगले साल फिर बढ़कर 6.6% हो सकती है। यह अनुमान उस समय के हालात पर आधारित है जब ईरान युद्ध चल रहा था और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज पर असर पड़ने लगा था। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। चीन की ग्रोथ इस साल 4.3% रहने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ और कमजोर रह सकती है।

ईपीएफओ की सहारा इंडिया पर सख्त कार्रवाई

लखनऊ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सहारा इंडिया की विभिन्न इकाइयों के खिलाफ भविष्य निधि (पीएफ) बकाया को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ईपीएफओ ने सहारा से करीब 1,204 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है। लखनऊ स्थित ईपीएफओ कार्यालय के अनुसार, अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023 के बीच सहारा समूह की कई यूनिट्स के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। ये सभी मामले ईपीएफ अधिनियम के तहत आते हैं। वसूली के आंकड़ों में चार बड़े दावे शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा दावा 1,179 करोड़ रुपए से अधिक का है। अन्य दावों की रकम 31 लाख रुपए से लेकर 23 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है।

सही रास्ते पर है भारतीय अर्थव्यवस्था

अभिजीत मुखोपाध्याय

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है, जो जनवरी के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। इसका कारण अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किये जाने से मिलने वाले लाभ को माना गया है। विश्व बैंक ने भी भारत की आर्थिक विकास दर को 6.5 फीसदी के अपने पहले के अनुमान से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पश्चिम एशिया संकट से तेल, गैस की महंगाई को रेखांकित करते हुए बताया गया है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था व मांग बुनियादी रूप से मजबूत बनी हुई है तथा जीएसटी में कटौती जैसे कदम विकास को गति दे रहे हैं। भारत से जुड़े विश्व बैंक और आइएमएफ के नवीनतम आंकड़े मजबूती की कहानी बताते हैं। यानी, उथल-पुथल के बावजूद भारत मजबूती से बढ़ रहा है।

आइएमएफ की इसी महीने आयी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' में आगामी वित्त वर्ष में भी भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत पर बने रहने की बात कही गयी है। वैश्विक वृद्धि दर इस वर्ष 3.1 प्रतिशत तक धीमी रहने के अनुमान के बीच आइएमएफ भारत को विश्व की सबसे टिकाऊ आर्थिक शक्तियों में से एक मानता है। भारत से जुड़ा आइएमएफ का आकलन आंकड़ों में भले छोटा हो, पर संकेत के रूप में महत्वपूर्ण है। और संकेत यह है कि भारत वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। गौर करने की बात है कि आइएमएफ का अप्रैल अपडेट युद्ध संबंधी बाधाओं, व्यापारिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति के दबावों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसने दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के

प्रति भरोसा कम किया है।

ऐसे में, भारत की मजबूत वृद्धि दर दर्शाती है कि घरेलू मांग, नीतिगत निरंतरता और संरचनात्मक मजबूती उसे सहारा दे रही है। आइएमएफ के मुताबिक, भारत 'मजबूत' स्थिति में है, जो बाहरी अस्थिरता को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि, विश्व बैंक और आइएमएफ के इन अनुमानों में मुद्रास्फीति की चुनौती भी हो सकती है। जैसे, आइएमएफ ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि 2025 में यह दर 2.0 फीसदी से नीचे रही थी। इसका मतलब यह है कि हालिया आपूर्ति शृंखला समस्याओं के कारण दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह दर अब भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सहनीय सीमा के भीतर रहने की संभावना है। यानी, अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति की चुनौती तो है, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है।

हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में भारत की स्थिति बदल गयी है। लेकिन जीडीपी रैंकिंग में भारत का छठे स्थान पर आना यह नहीं दर्शाता कि अर्थव्यवस्था की गति अचानक धीमी हो गयी है। दरअसल, वैश्विक जीडीपी रैंकिंग अमेरिकी डॉलर में मापी जाती है, इसलिए जब रुपया कमजोर होता है, तब डॉलर के संदर्भ में भारत की जीडीपी छोटी दिखती है, भले ही रुपये में उत्पादन बढ़ रहा हो। कई रिपोर्टों के अनुसार, 2026 में रुपये के अवमूल्यन ने भारत की डॉलर जीडीपी को कम दिखाया, जबकि पाउंड और येन अपेक्षाकृत मजबूत रहे, जिससे ब्रिटेन और जापान रैंकिंग में आगे निकल गये।

इसलिए यह बदलाव मूलभूत कमजोरी नहीं, बल्कि मुद्रा विनिमय का प्रभाव है। रैंकिंग में अस्थायी गिरावट को वैश्विक मुद्रा बाजारों के प्रभाव के रूप में देखना चाहिए, न कि भारत की आर्थिक दिशा पर अंतिम निर्णय के रूप में। इन सभी बातों से तीन प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, भारत की विकास की कहानी अब भी मजबूत है- कमजोर वैश्विक माहौल में साढ़े छह फीसदी या उससे अधिक की संभावित वृद्धि दर हमारी आर्थिक शक्ति का संकेत है। दूसरा, भारत की वैश्विक स्थिति अब विनिमय दर में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गयी है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि छोटी मुद्रा चालें भी डॉलर आधारित तुलना को प्रभावित करती हैं।

महिला आरक्षण बिल के पारित नहीं होने पर भाजपा का गुस्सा बरकरार

ऐतिहासिक गलती के लिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं कांग्रेस को कभी नहीं करेंगी माफ

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने से पहले ही भाजपा नेताओं का गुस्से पर आज छत्तीसगढ़ पहुंची कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। यह गुस्सा उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान में साफ नजर आया, जब उन्होंने बिल पारित होने को कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती करार देते हुए कहा कि इसके लिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने पर कहा कि वास्तव में देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा हुआ है। दशकों तक नारी शक्ति को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा

में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जिसने संसद में बिल के खिलाफ समर्थन कर छत्तीसगढ़ के माताएं और बहनों को अधिकार से वंचित किया।

साव ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ और छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ धोखा हुआ है। भविष्य में कांग्रेस को यह बहुत भारी पड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ की माताएं-बहनें कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उनके अधिकारों से वंचित करने वाली ही आज इस विषय में सवाल करने आ रही है, ये कितनी हास्यास्पद बात है। उन्हें तो पहले छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सवालों का जवाब देना होगा।

नगरीय निकायों के कार्यों की मैराथन समीक्षा का दूसरा दिन

रायपुर। प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। श्री साव ने कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने को कहा।

महिला आरक्षण पर विधानसभा विशेष सत्र बुलाएगी साय सरकार

रायपुर। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने इसके विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। राजधानी रायपुर में भी भाजपा ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया।

रैली के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से बातचीत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को पास कराने में विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही विशेष सत्र बुलाएगी, जो संभवत: 29 अप्रैल से पहले आयोजित किया जाएगा और एक दिवसीय होगा।

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार

महिलाओं के हित में फैसले लेते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कारण यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं और जनता का विश्वास एनडीए सरकार पर बना हुआ है।

गौरतलब है कि हाल ही में संसद के विशेष सत्र में लाया गया संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इस पर करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद मतदान हुआ, जिसमें 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि पारित होने के लिए 352 वोट जरूरी थे। इस तरह यह विधेयक 54 वोट से गिर गया।

इस बीच, राज्य में पहले भी कई अहम मौकों पर विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं, जिनमें 2013 में झीरम घाटी हमले के बाद, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर और 2025 में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर शामिल हैं।

भीषण गर्मी से बिजली ठप होने का खतरा

बिजली विभाग ने लगाया जुगाड़, ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा रखने लगाया कूलर

रायपुर। भारत की झुलसाती गर्मी का असर अब सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, अब बिजली के ट्रांसफॉर्मर भी इस गर्मी से पसीना-पसीना हो गए हैं। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। तेज गर्मी के चलते बिजली उपकरणों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बिजली विभाग ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

बता दें कि शहर के सिविल लाइन स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में लगे ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाया गया है, ताकि अत्यधिक तापमान के कारण ट्रांसफॉर्मर ओवरहीट न

हो।

दरअसल, जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बिजली की खपत भी आसमान छू रही है। इससे ट्रांसफॉर्मरों पर लोड बढ़ता है और वे ज्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्मी के कारण कई बार वोल्टेज लो हो जाता है और ट्रांसफॉर्मर ट्रिप या फट भी सकते हैं।

ऐसे में आग लगने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए यह प्रयोग किया गया है, जिससे ट्रांसफॉर्मर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके।

बिजली विभाग के इस कदम को गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना के मद्देनजर विभाग अन्य जरूरी इंतजाम भी करने की तैयारी में है।

सूरजपुर बना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्रदेश का अग्रणी जिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हैं। वित्तीय वर्ष 2024-26 अंतर्गत राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता जिला कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले के विशेष प्रयासों का परिणाम है।

गौरतलब है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिले में कुल 72,368 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से अब तक 63,947 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जो कि 88.36% की प्रभावशाली उपलब्धि को दर्शाता है। यह आंकड़ा न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक ठोस

कदम भी है। वित्तीय प्रबंधन के स्तर पर भी सूरजपुर जिला अग्रणी रहा है।

आवास निर्माण के लिए निर्धारित 868.42 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 809.23 करोड़ रुपये, अर्थात् 93.18 प्रतिशत राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और निर्माण कार्य में तेजी आई है। इसके साथ ही, जिले में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास प्लस 2.0 के तहत 1.40 लाख से अधिक परिवारों का नवीन सर्वे भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिससे आने वाले समय में और अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

जिला प्रशासन की सक्रियता, जमीनी स्तर पर निरंतर निगरानी, और हितग्राहियों की सहभागिता ने इस योजना को एक जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। आज सूरजपुर जिले के हजारों परिवार अपने पक्के घर का सपना साकार होते देख रहे हैं।

वेदांता प्लांट हादसे की सुनवाई 29 को करेंगे बिलासपुर संभाग आयुक्त

बिलासपुर। सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे की जांच सार्वजनिक भागीदारी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में बिलासपुर संभाग आयुक्त कार्यालय ने 29 अप्रैल को साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी दौरान संभायुक्त सुनवाई करेंगे। इस दौरान इच्छुक व्यक्ति, प्रभावित पक्ष या संगठन निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित होकर अपने तथ्य, दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पहल जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से की गई है।

आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, 14 अप्रैल को प्लांट के यूनिट-1 के बॉयलर सेक्शन में स्टीम पाइप से जुड़ी वाटर सप्लाई लाइन के जॉइंट में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई थी। इस घटना में 24 श्रमिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने बिलासपुर संभाग के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करें, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस प्रक्रिया के जरिए न केवल दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जाएगा, बल्कि जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके लिए प्रत्यक्षदर्शियों, श्रमिकों, प्रबंधन से जुड़े लोगों और अन्य संबंधित पक्षों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाये भाजपा सरकार

रायपुर। भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाये जाने के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा को निंदा प्रस्ताव लाना है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ और केन्द्र सरकार के खिलाफ निंदा

प्रस्ताव ले आये। भाजपा एक ऐसा विधेयक जो संसद के दोनो सदनों में पारित हो गया है तथा जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तथा वह कानून का रूप ले चुका है। उस पर झूठ बोल कर भ्रम फैला रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू नहीं करने के लिये मुख्यमंत्री मोदी की दुर्भावना के लिये निंदा प्रस्ताव ले आये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महिलाओं को आरएसएस भाजपा में लंबे समय तक उपेक्षित रखने तथा उनके बारे में दोयम दर्जे का विचार रखने के लिये आरएसएस एवं भाजपा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिये। कांग्रेस ने इस देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पहली लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अनेक अवसर दिया। भाजपा ने तो केवल महिलाओं का अपमान किया है।

व्यापम की परीक्षाएं अब प्रातः 10 बजे से, दिशा निर्देश जारी

रायपुर। प्रदेश में बढ़ते तापमान को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिये समय प्रात: 10 से 12.15 बजे तक निर्धारित किया गया है। आगामी 26 अप्रैल 2026 को व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में भी यही समय लागू होगा। जारी दिशा निर्देश अनुसार परीक्षार्थी, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 9.30 बजे बंद कर दिया जायेगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देना होगा। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी।परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णत: वर्जित है।

सुशासन शिविर की तैयारी निर्धारित अवधि में पूरी करें

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मंगलवार

को रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार 1 मई 2026 से सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाएंगे। सभी नगरीय निकाय और जनपद पंचायत के अधिकारी इस संबंध में सारी तैयारी निर्धारित अवधि में पूरी कर लें। कलेक्टर ने कहा कि 24 अप्रैल 2026 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर दीनदयाल सभागृह में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रमुख प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों को इस कार्यक्रम हेतु समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में हीट वेव चलने की संभावना है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयों का इंतजाम बनाए रखें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर एवं एडीएम श्री उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों से खाद छीनने का षड्यंत्र बेनकाब : सुरेंद्र वर्मा

रायपुर। खाद्य वितरण के लिए फार्मर आईडी

के अनिवार्यता को किसान विरोधी षड्यंत्र करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के 9 लाख से अधिक किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन रोक कर समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित किया था इस तरह से अब उन किसानों को खाद से भी वंचित करने का तुगलक की फरमान जारी किया गया है। सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ यूरिया डीएपी एनपीके और पोटाश जैसे खाद मिलने में दिक्कत होगी बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी से भी किसान वंचित कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी समिति में कुल 40 लाख 89 हजार 908 किसान पंजीकृत शेयर होल्डर हैं, फार्मर आईडी बनाने के लिए एग्री स्टेक परियोजना में अब तक मात्र 31 लाख 68 हजार 555 किसानों का सत्यापन हुआ है इस प्रकार से लगभग 21 प्रतिशत किसान पंजीयन से वंचित हैं। सरकार छत्तीसगढ़ के इन 9 लाख 21 हजार 353 किसानों को खाद नहीं देना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार 41,500 करोड़ की 'अतिरिक्त खाद सब्सिडी' का ढिंढोरा पीट रही है।

लखनपुर को मिलेगा बाईपास, बनेगी वन्यजीव-अनुकूल फोरलेन

रायपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर अंबिकापुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन प्रोजेक्ट में अहम बदलाव किए गए हैं। अब इस परियोजना में लखनपुर नगर के लिए बाईपास निर्माण और लेमरू क्षेत्र में वन्यजीव-अनुकूल सड़क तैयार की जाएगी। दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग-130 को फोरलेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और इसके लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा रही है। यह मार्ग सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा जिलों के घने वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसमें लेमरू हाथी प्रोजेक्ट क्षेत्र भी शामिल है। लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बाईपास नहीं होने के कारण भारी वाहन शहर के बीच से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सिंहदेव ने 8 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बाईपास निर्माण की मांग की थी। टी.एस. सिंहदेव ने अपने सुझाव में लेमरू क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उन्होंने भारतमाला परियोजना के मानकों के अनुसार सड़क निर्माण करने का सुझाव दिया, जिसमें एनिमल बैरिकेडिंग और पर्याप्त अंडरपास जैसी सुविधाएं शामिल हों, ताकि वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित न हो।

महिला आरक्षण : रंजीत रंजन एवं कांग्रेस की महिला विधायकों की पत्रकार वार्ता

मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, वह महिलाओं को ठग रही

रायपुर। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन एवं महिला विधायकों ने पत्रकार वार्ता लेकर महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की दुर्भावना पर कड़ा प्रहार किया। राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक झूठ बोल रहे है। भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार झूठा भ्रम फैलाया जा रहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए संसद में बिल पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) 128 वां संविधान संशोधन सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर चुकी है तथा यह कानून भी बन चुकी है। भाजपा 2023 के आरक्षण बिल को क्यों लागू नहीं कर रही है? इस बिल के आधार पर तुरंत आरक्षण प्रभावी हो सकता है। भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 131 वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं भाजपा महिला आरक्षण

को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी।

राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने कहा कि संसद में जो विधेयक गिरा उसमें इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था राज्यों में 815 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें। परिसीमन विधेयक- जिसमें परिसीमन के लिये 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की गयी थी। विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन की बात की गयी थी ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सके। जब 2026-27 की जनगणना शुरू है तथा सरकार जाति जनगणना की भी बात कर चुकी है तो जनगणना के बाद आये नये आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा?

राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन एवं महिला विधायकों ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को यदि तुरंत लागू करना है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत का आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती सरकार? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार है। सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कानून बन चुका है 2034 से मूर्त रूप लेगा संशोधन से तुरंत लागू हो जाता। भाजपा की मंशा महिला आरक्षण की नहीं अपने मनमुताबिक सीटों के परिसीमन की थी जो विपक्षी दलों की एकजुटता से पूरा नहीं हो चुका।

राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन एवं महिला विधायकों ने कहा कि पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा तो यह भी कांग्रेस की नीतियों से संभव हो पाया। सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका। अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। कांग्रेस की सरकारों के प्रयास से ही आज देशभर में पंचायतों और नगरपालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। सीटों के परिसीमन का भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया है, अत: वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है।

पत्रकार वार्ता में विधायक गण अनिला भेड़िया, अंबिका मरकाम, संगीता सिन्हा, सावित्री मंडावी, चातुरी नंद, शेषराज हरवंश, हर्षिता बघेल, कविता प्राण लहरे, विद्यावती सिदार, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत, प्रीति उपाध्याय, प्रगति वाजपेयी उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.